प्रभात

अंदर के पन्नों में...
★ विधान सभा चुनाव नतीजें 6
★ विधानसभा चुनाव बहिष्कार रिपोर्ट 10
★ पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ 13
★ दुश्मन बलों पर पीएलजीए हमलें 17
★ फर्जी मुठभेड़ें 20
★ सड़क के चौड़ीकरण के विरोध में 23
★ सरकारी दमन 27
★ नसीरुद्दीन शाह की बातों पर... 30

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख–पत्र
वर्ष–31 अंक–4 अक्टूबर–दिसंबर 2018 सहयोग राशि–15 रुपए

झूठे लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करो!

जनताना सरकारों को मजबूत करो एवं उनका विस्तार करो!

नवजनवादी क्रांति को सफल बनाएं!

17 वें लोकसभा चुनावों की नौटंकी फिर से जोर पकड़ी है. लोकसभा चुनावों के साथ आंध्रप्रदेश, ओड़िशा, सिक्किम और अरुणाचलप्रदेश विधानसभाओं के लिए, अप्रैल–मई 2019 में चुनाव होने वाले हैं.

लोगों को दिग्भ्रमित करने, लुभाने व भटकाने के जरिए वोट एवं सीट पाने भाजपा, कांग्रेस समेत सभी संसदीय दलों ने अपनी–अपनी कवायदें तेज की हैं. हमारे देश का संसदीय जनवाद झूठा है. साम्राज्यवादियों के बीच एवं देश के दलाल नौकरशाही पूंजीपति और बड़े सामंती वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न राजनीतिक पार्टियों (शासकीय गुटों) के बीच प्रतिस्पर्धा की अभिव्यक्ति के तौर होने वाले इन धोखेबाजीपूर्ण और कपटतापूर्ण चुनावों का मुख्य उद्देश्य यह तय करना कि किस शासकीय गुट सत्तासीन होकर और पांच सालों तक साम्राज्यवादियों और देश के शोषक वर्गों के हित पूरा करने के लिए व्यापक जनसमुदायों पर अपना क्रूर शासन जारी रखेगा. इसीलिए मार्क्स और एंगेल्स ने स्पष्ट किया कि ''संसदीय रूप नकाब पहने बुर्जुआ वर्ग की तानाशाही ही है'' और ''आधुनिक राज्य की कार्यपालिका पूरे बुर्जुआ वर्ग के सामान्य मामलों का संचालन करने वाली समिति के अलावा और कुछ नहीं है''.

दरअसल वर्तमान में हमारे देश में नए औपनिवेशिक रूप के साम्राज्यवादी परोक्ष शासन, शोषण और नियंत्रण के तहत अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामंती व्यवस्था अस्तित्व में है.

यह सभी को ज्ञात है कि 2014 में हुए संसदीय चुनावों में – कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(यूपीए)–2 की सरकार के प्रति जनता में व्याप्त असंतोष, आक्रोश और विरोध का इस्तेमाल कर, साम्राज्यवादियों और देशी–विदेशी कॉर्पोरेट अरबपतियों के बल पर, कॉर्पोरेट मीडिया द्वारा किए गए जोर–शोर के प्रचार व शब्दाडंबर के साथ, हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने, कालाधन को बाहर निकालने, किसानों की आय दोगुनी करने, गंगा नदी की सफाई करने आदि कई जनाकर्षक वादों की झड़ी लगाकर जनता के अंदर भ्रम फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सत्तासीन हुआ. एनडीए ने सिर्फ लोकलुभावन वादें ही नहीं किए बल्कि देश के बहुल आबादी हिंदू लोगों के वोट पाने के लिए अयोध्या में राममंदिर और जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा–370 को हटाने आदि हिंदू धर्मांधता को भड़काने वाले वादें भी किए.

भाजपा ने साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) के आदेशों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए–2 द्वारा लागू नयी उदारवादी नीतियों का ही अनुसरण करते हुए उन नीतियों को और गति दी है. वह किसी भी चुनावी वादे को पूरा नहीं कर पायी, बल्कि जनता पर शोषण और उत्पीड़न को उसने और तेज किया है. मोदी सरकार की नीतियों के कारण रुपये का मूल्य डालर के मुकाबले 73 रुपये तक घट गया है. भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा दिया गया. मोदी के शासन में हाल ही में अत्यधिक क्षेत्रों में एफडीआई के लिए 100 प्रतिशत अनुमति मिली है. औद्योगिक और कृषि संकट गंभीर स्तर तक पहुंच गया है. किसानों को दिए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं आय को दोगुनी करने के वादों को मोदी सरकार ने कूड़ेदान में डाल दिया है. बैंकों के हजारों करोड़ रुपये लूटने वाले ललित मोदी, मेहुल चौक्सी, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को सुरक्षित देश से बाहर भेज दिया है. हर वर्ष के बजट में कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए लाखों करोड़ रुपयों की टैक्स रियायत (आर्थिक वर्ष 2015–16 और 2016–17 में ही 12 लाख करोड़ रुपये) दी जा रही है. उन कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए एक लाख 32 हजार करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर दिया गया है. लेकिन कर्ज से दबकर बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं करने वाले किसानों को राहत के रूप में मोदी सरकार ने एक पैसे का कर्ज भी माफी नहीं किया.

तैयारी (मैनुफक्चरिंग) उद्योग रोज–रोज कमजोर हो रहा है. देश का व्यापार घाटा बढ़ रहा है. देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, आवासहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, साफ पेयजल का अभाव, अस्वस्थता, महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ गयी हैं. इस कारण लाखों की तादाद में लोग रोजी रोटी के लिए विदेशों, शहरों या दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, जहां वे अकथनीय शोषण, उत्पीड़न और अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं. मानव तस्करी के जाल में विशेषकर दलित और आदिवासी युवतियां फंस रहे हैं. देश भर में भुखमरी और आत्महत्याएं बढ़ रही हैं. नोटबंदी और जीएसटी ने गरीबों, मंझोले वर्ग के लोगों व युवाओं व छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ दी है. नोटबंदी के चलते जीडीपी की वृद्धि 1 प्रतिशत घटी और 15 लाख नौकरियां चली गईं. 3 लाख छोटे व मध्यम उद्योग बंद हो गए.

कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी के अच्छे दिन अंबानी, अदानी आदि के लिए हैं. आम आदमी को सबसे बुरे दिन झेलना पड़ रहा है. प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात तो कोसों दूर, जन धन योजना आदि के नाम पर अभी सभी के खातों की रकम को पूंजीपतियों के लिए लुटाया जा रहा है और खातों में विदेशी कर्ज चढ़ाया गया है. 2018–19 के केंद्रीय बजट के अनुसार देश का कुल कर्ज लगभग 90 लाख करोड़ रुपयों तक पहुंच गया. इसका मतलब है कि अभी जन्म लेने वाले शिशु के सिर पर भी लगभग 75 हजार रुपयों के कर्ज का बोझ है. पूंजीपतियों के लिए लाखों करोडों की कर्ज माफी, किसानों के लिए आत्महत्याएं.

सरकार की जन विरोधी व देशद्रोही नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशद्रोही करार दिए गए, सलाखों के पीछे डाल दिए गए एवं मरवाए गए. नया भारत के नाम पर ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भारत का निर्माण करने पर तुली हुई है. गोरक्षा के नाम पर दलितों, मुसलमानों व आदिवासियों के खान–पान की आदतों पर पाबंदियां लगायी जा रही हैं. उनकी सरे राह गोगुंडों द्वारा हत्याएं की जा रही हैं. घरवापसी, लवजिहाद आदि नामों पर भी हमलें व हत्याएं जारी हैं.

हिंदू फासीवादियों द्वारा देश में फैलाए जा रहे असहिष्णुता के माहौल के खिलाफ आवाज उठाने वालों के ऊपर हमलें किए जा रहे हैं. कलबुर्गी, गोविंद पन्सरे, नरेंद्र धाबोल्कर,गौरी लंकेश जैसे प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष व जनवादी प्रेमियों की हत्याएं की गई.

महिलाओं की सुरक्षा तो बड़े खतरे में है. कठुआ व उन्नाव बलात्कार कांडों में भाजपाई न सिर्फ अपराधी ठहराए गए बल्कि अपराधियों के बचाव में मंत्रियों सहित बहुत सारे लोग बेशर्मी से आगे आए. कई विश्वविद्यालयों

मोदी के राज में किसान सड़क पर

कर्जमाफी, फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य व तमाम मांगों को लेकर 30 नवंबर को नई दिल्ली में रामलीला मैदान से संसद की ओर मार्च करते देश भर से आए किसान.

में ड्रेस कोड के रूप में महिलाओं पर पाबंदियां लागू की जा रही हैं. आरएसएस की कई अनुषांगिक संस्थाओं के जरिए ब्राह्मणीय विचारधारा के अनुरूप महिलाओं को ढालने की कोशिश की जा रही है. महिलाओं को शबरिमला मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने तो दी. लेकिन मनु के वारिसों ने नहीं दी. इस मौके पर कई महिलाओं पर हिंदू कट्टरपंथियों ने हमलें किए.

फासीवादी शासकों द्वारा अखंड भारत का नारा लगाते हुए कश्मीर व पूर्वोत्तर की राष्ट्रीयताओं की जनता की राष्ट्रीय मुक्ति आकांक्षाओं को कुचल दिया जा रहा है. कश्मीर में राज्यपाल के शासन के रूप में केंद्र सरकार का शासन चल रहा है. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि कई लोकलुभावन योजनाओं, जुमलों, कोरी लफ्फाजी, अनर्गल बातों के जरिए विकास का बहाना करते हुए लोगों को दिग्भ्रमित कर देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों की सेवा व गुलामी व उनकी संपत्ति एवं लूट का चौकीदार बना हुआ है, देश के प्रधान मंत्री पद पर बैठा नरेंद्र मोदी. देश के अंदर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे नयी प्रौद्योगिकी (टेकनोलोजी) घुसने के कारण भी नौकरियों में कमी आई है. ठेका मजदूर व्यवस्था और आउटसोर्सिंग में बढ़ोत्तरी हुई है. तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से हाथ खींचने नयी व धोखेबाजीपूर्ण नीतियों की घोषणाएं की जा रही हैं. बजट में निधियों के आवंटन में लगातार कटौती की जा रही है. भ्रष्टाचार व घोटालों का अंबार लगा है. 58,000 करोड़ रुपयों के राफेल युद्ध विमानों की खरीद के मामले में देश के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले का उजागर होना मोदी के भ्रष्टाचारी शासन का छोटा उदाहरण मात्र है.

देशी, विदेशी कॉरपोरेट लूट को बेरोकटोक जारी रखने, उसके लिए आवश्यक बड़ी खनन, भारी औद्योगिक, बांध परियोजनाओं को जबरन व जन विरोध को दबाकर शुरु कराने दंडकारण्य समेत संसाधन बहुल वन इलाकों जोकि सशस्त्र संघर्ष के इलाकें भी हैं, में लगातार पुलिस व अर्ध सैनिक बलों की तैनाती को बड़े पैमाने पर बढ़ाते हुए जन दमन की पाशविक योजना समाधान पर बर्बर तरीके से अमल किया जा रहा था. छत्तीसगढ़ में अपने 15 वर्षीय कार्यकाल में भाजपा सरकार ने गोंपाड, सिंगारम, ताकिलोड, सार्किनगुडा, एड्समेट्टा, नुल्कातोंग आदि नरसंहारों को अंजाम दिया.

भीमा कोरेगांव के 200वें वार्षिक स्मृति दिवस के अवसर पर हुए जन प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं करने वाले हिंदू फासीवादी तत्वों ने उस पर महाराष्ट्र राज्य सरकार के बल पर पाशविक रूप से हमलें किए हैं. इन अपराधियों

मराठवाड़ा में 11 माह में 855 किसानों ने की आत्महत्या

महाराष्ट्र के मराठवाडा में किसान आत्महत्याओं का सिलसिला थमता नहीं दिखाई दे रहा है. फसलों पर लगने वाले रोग, बारिश की कमी से होने वाला फसलों का नुकसान और सर पर बढ़ता हुआ कर्ज, फसल की पैदावार में भारी कमी से किसानों में भारी निराशा घर कर गई है और वे खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं. जनवरी से लेकर नंवबर तक की अवधि में 855 किसानों ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर डाली. इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर 532 मामले वैध और 240 मामलों को अवैध घोषित किया गया है, जबकि 83 मामले जांच के लिए प्रलंबित हैं. सूखाग्रस्त मराठवाडा में पिछले चार से पांच वर्ष से बारिश काफी अनियमित रही है. इस बार भी सूखे के कारण हजारों हेक्टयर जमीन पर फसल सूख रही है. फसल पर होने वाली बीमारियों और सहूकार से लिए कर्ज को वापस कैसे लौटाया जाए, इसकी चिंता किसानों को सता रही है.

– नवभारत से साभार

गोकशी के बहाने बुलंदशहर में भड़की हिंसा, इस हिंसा में पुलिस के एक अधिकारी की मौत भी हुई

पर कोई कार्यवाही नहीं की गई. इसके विपरीत मोदी की हत्या करने की साजिश का बहाना बनाकर देशभर में दलित, जनवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर मोदी के भाड़े के पुलिस बलों द्वारा यूएपीए जैसे क्रूर कानून लगाकर उन्हें जेलों में ठूंसकर, देश में आतंक मचाया गया. केंद्र की तर्ज पर महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार भी राज्य के संसाधनों को देशी, विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर रही है और दूसरी ओर कल्लेडा, हल्बी–तुम्मीरगुंडा जैसी मुठभेड़ों, झूठी मुठभेड़ों को अंजाम देते हुए संघर्षरत पार्टी, पीएलजीए व जनता पर पाशविक दमन जारी रखी हुई है.

लेकिन शोषण व उत्पीड़न के विरोध में एवं अपनी तबकाई समस्याओं को लेकर विभिन्न उत्पीड़ित वर्गों व तबकों की जनता एवं अपनी अस्मिता, अस्तित्व व आत्मसम्मान एवं अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, ब्राह्मणीय हिंदुत्व धर्मोन्माद के विरोध में दलित, आदिवासी, मुसलमान व ईसाई समेत अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों के लोग लगातार सड़कों पर बड़े पैमाने पर उतर रहे हैं. ज्ञात रहे, मोदी के शासन के शुरु होने के बाद एक वर्ष के भीतर ही देश में बढ़ रही असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाते हुए 100 से अधिक जाने माने लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों द्वारा अपने पुरस्कारों को लौटाने की अभूतपूर्व प्रतिक्रिया दिखाई दी.

पांचवीं अनुसूची वाले इलाकों के आदिवासी अवाम पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं के अधिकारों के लिए जोरदार संघर्ष कर रहा है जोकि उत्तर छत्तीसगढ़ में पत्थलगड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है.

हाल ही में पांच राज्यों में आयोजित चुनावों में भाजपा को मिली हार द्वारा साढ़े चार सालों के एनडीए शासन पर जनता के आक्रोश को कुछ हद तक समझ सकते हैं.

देश भर में उठ रहे विरोध को भांपते हुए आगामी चुनावों में दोबारा सत्ता दखल करने के लिए मोदी और भाजपा के नेता अपने तेवर को और आक्रामक बना रहे हैं. देशभक्ति के नाम पर देश में अंधराष्ट्रवाद, ब्राह्मणीय हिंदुत्व कट्टरता के जरिए नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं और फैला रहे हैं.

अब कांग्रेस पार्टी के बारे में देखे, तो उसने देश में तथाकथित आजादी के बाद से सबसे ज्यादा समय तक सत्ता की बागडोर संभाले रखी थी और वह जन विरोधी, देश द्रोही व जन दमनकारी नीतियों पर अमल करती रही. कश्मीर, पूर्वात्तर राष्ट्रीयताओं के आंदोलनों समेत तेलंगाना, नक्सलबाड़ी व श्रीकाकुलम के किसान सशस्त्र आंदोलनों को खून की नदी में डुबोने का इतिहास रहा है, कांग्रेस का 1984 के सिखों के कत्लेआम सहित कांग्रेस/यूपीए के शासन में मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं पर अत्याचार और हत्याकांडों को अंजाम दिया गया. आज देश में किसानों की आत्महत्याओं का जो सिलसिला जारी है वह कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में लायी गई नयी उदारवादी नीतियों की देन है. अपना अपराध पर नकाब डालते हुए आज किसानों की कर्ज माफी की बात कांग्रेस कर रही है. वह कुछेक संसदीय पार्टियों के साथ महागठबंधन बनाकर चुनावों में बहुमत प्राप्त करने का सपना देख रही है.

15 साल के लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार अपनी पूर्ववर्ती भाजपा की तमाम जन विरोधी व कॉरपोरेटपरस्त एवं जन दमनकारी नीतियों पर बेरोकटोक अमल कर रही है.

अब बाकी पार्टियों के बारे में देखा जाये तो, देश में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ–साथ, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम और वाइ.एस.आर. कांग्रेस, तेलंगाना में टीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओड़िशा और कर्नाटक में अलग–अलग पार्टियों और

ग्रुपों के रूप में मौजूद जनतादल, पश्चिम बंगाल में तृणमुल कांग्रेस पार्टी, कश्मीर में नेशनल कान्फरेंस, पीपुल्स डेमोक्रटिक पार्टी, असम में असम गण परिषद, मिजोराम में मिजो नेशनल फ्रंट, छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस आदि पार्टियां मुख्य रूप में साम्राज्यवाद की ही दासता करते हुए, दलाल नौकरशाही बुर्जुआ और बड़े सामंती वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां ही हैं. इनमें से अधिकतर पार्टियां विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयता आकांक्षाओं का, दलित, बहुजन लोगों की मुक्ति की आकांक्षाओं का इस्तेमाल करते हुए अपना समय चला रही हैं. इनके अलावा, भाकपा (मार्क्सवादी) और भाकपा जैसी संशोधनवादी पार्टियां उत्पीड़ित जनता और तबकों के आंदोलनों को क्रांति के रास्ते से भटकाने का काम कर रही हैं. इसमें भाकपा (मार्क्सवादी) ने पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में जब सत्ता में होती है, तब जनांदोलनों को कुचलने में लगी रहती है, जब विपक्ष में होती है, तब राजनीतिक रूप से जनता के पक्ष लेने में अवसरवादी रुख अपनाती है. यह हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने में मुख्य पार्टियों के साथ होड़ में लगी हुई है. ये सभी पार्टियां साम्राज्यवाद और लुटेरे वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए प्रतिक्रियावादी भूमिका निभा रही हैं.

हमारे देश की अर्ध–औपनिवेशिक और अर्ध–सामंती लुटेरी व्यवस्था के स्थान पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता व मानवता–युक्त समाज अपने आप उभरकर आना संभव नहीं है. देश की पूरी संपदाओं को जिस तरह इस देश के लोग पैदा कर रहे हैं, उसी तरह शोषण और उत्पीड़नविहीन समाज को भी अपने आत्मगत प्रयास के जरिए उत्पीड़ित वर्गों व तबकों की जनता को ही निर्मित करना होगा. इस महान कार्य को कोई भी राजनीतिक पार्टी कार्यान्वित कर सकती है, इसके लिए इंतजार करना

फर्जी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करें!
जनताना सरकारों की स्थापना करें, उनका विस्तार करें!
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

सिर्फ भ्रम ही होगा.

आइए! झूठे चुनावों का बहिष्कार कर, हमारे देश में मौजूदा लुटेरी व्यवस्था जो दलाल नौकरशाह पूंजीपति और बड़े सामंती वर्गों को और उनके साम्राज्यवादी मालिकों का प्रतिनिधित्व करती है, को उखाड़ कर उसकी जगह में सच्ची जनवाद और स्वावलंबन की बुनियाद पर भारत की जनता के जनवादी गणतंत्रों के संघ के निर्माण के लिए, जोतने वालों को जमीन के नारे लेकर, कृषि क्रांति की धुरी पर, नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने के लक्ष्य से, सर्वहारा के नेतृत्व में, मजदूर–किसान की मित्रता के आधार पर मजदूर, किसान, निम्नपूंजीपति वर्ग, देशीय बुर्जुआ वर्गों के साथ क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा की बुनियाद पर जारी दीर्घकालीन लोकयुद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा लें. जनता की समस्याओं के हल के लिए चुनाव नहीं, बल्कि संघर्ष ही एक–मात्र रास्ता है. देशभर में जनता की क्रांतिकारी राजसत्ता को स्थापित कर, दीर्घकालीन लोकयुद्ध को अंतिम जीत की तरफ आगे बढ़ाना ही जनमुक्ति का रास्ता है.

इसी रास्ते पर दंडकारण्य की संघर्षरत जनता आगे बढ़ रही है. दंडकारण्य में शोषक–शासक वर्गों को उखाड़ फेंक कर क्रांतिकारी जनताना सरकारों, जिसके द्वारा यहां की जनता के आर्थिक स्वावलंबन व असली विकास को हासिल करने, राजनीतिक चेतना बढ़ाने, अस्मिता व आत्मसम्मान को बचाने, संस्कृति को विकसित करने, प्राकृतिक संपदाओं व संसाधनों को बचाने की कोशिश जारी है, का निर्माण व उनका विस्तार करने का प्रयास जनयुद्ध व जन संघर्ष के जरिए कर रही है. इसी सिलसिले में हर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों का बहिष्कार कर रही है. ठीक इसी तरह इस बार भी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करें और क्रांतिकारी जनताना सरकारों का निर्माण और उनका विस्तार करने में आगे बढ़ें. ❍

विधान सभा चुनाव नतीजें
भाजपा की हार – जनविरोधी नीतियों का अपरिहार्य परिणाम!

दिसंबर 12 को पांच राज्यों – छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना व मिजोरम के विधान सभा चुनावों के नतीजें घोषित हो गए हैं. छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राज्यों में पिछले 15 सालों से एवं राजस्थान में पिछले 5 सालों से सत्तारूढ़ ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भाजपा को चुनावों में मुंह की खानी पड़ी. जबकि तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस की फिर से सत्ता में वापसी हुई और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट को बहुमत हासिल हुआ.

चुनाव नतीजों की खास बात यह रही कि देश के तीन भाजपा शासित प्रमुख राज्यों में भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत. ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी 'संघ' परिवार की भाजपा की मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों द्वारा पिछले 15 सालों से, राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 सालों से एवं केंद्र सरकार द्वारा पिछले साढ़े चार सालों से अमल सामंती, देशी–विदेशी कॉरपोरेट घरानापरस्त, देशद्रोही, जनविरोधी उदारीकरण–निजीकरण–भूमंडलीकरण की नीतियों को इन झूठे चुनावों के जरिए ही सही जनता ने सिरे से खारिज किया है.

जबकि भाजपा की कई जनविरोधी नीतियों का विरोध करते हुए, विभिन्न जन आंदोलनों, शिक्षक–कर्मचारी आंदोलनों के पक्ष में खड़े होने की नौटंकी करते हुए, अपने जनाकर्षक वादों से युक्त चुनावी घोषणापत्रों को सामने लाकर, जनता में व्याप्त भाजपा सरकार विरोधी माहौल को भुनाकर, मौजूदा चुनावी प्रहसन में जनता के सामने सही विकल्प के अभाव का फायदा उठाकर कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई.

जबकि तेलंगाना में टीआरएस प्रमुख केसीआर समय से पहले चुनाव करवाकर, कांग्रेस–तेलुगु देशम गठबंधन को निशाना बनाते हुए जनता को अपने जनाकर्षक योजनाओं व लोकलुभावन वादों से दिग्भ्रमित करने में एक बार और कामयाब हुए. यहां भाजपा को सिर्फ एक सीट मिली.

मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस के प्रति लोगों में व्याप्त एंटी इंकंबेंसी का फायदा उठाने में सफल रहा.

चुनाव नतीजों के विश्लेषण में जाने से पहले हमें इस सच्चाई से वाकिफ होना होगा कि उत्पीड़ित जनता की मूलभूत समस्याएं – भूमि, भुक्ति व विमुक्ति संसदीय चुनावों के जरिए हल नहीं होंगी. दरअसल ये चुनाव ही हर पांच साल में एक बार यह तय करने के लिए आयोजित किए जाते हैं कि आने वाले और पांच साल तक शोषक–शासक वर्गों का किस गुट उत्पीड़ित जनता पर अपना शासन व शोषण जारी रखेगा एवं जनता का दमन करेगा. सत्ता की बागडोर सौंपने के लिए किसी एक शोषक वर्गीय पार्टी को चुनने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं छोड़ने वाले ये चुनाव जनभावनाओं की वास्तविक अभिव्यक्ति कतई नहीं हैं. इस बुनियादी मार्क्सवादी समझ के साथ ही हमें राजनीतिक परिणामों के तहत होने वाले सभी चुनावों व उनके नतीजों का विश्लेषण करना चाहिए.

यह कह सकते हैं कि इन चुनावों में जनता की समस्याएं और मुद्दें जैसे किसानों, मजदूरों, युवाओं, छोटे कारोबारियों एवं मध्य वर्ग की ज्वलंत समस्याएं कुछ हद तक एजेंडे पर आई, चर्चा हुई लेकिन इनके वास्तविक हल के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा. जबकि कांग्रेस की ओर से सस्ती लोकप्रियता के वादों का मायाजाल बिछाया गया.

नोटबंदी व जीएसटी से उद्योग–धंधों की तबाही व रोजगार में गिरावट खासकर छोटे कारोबार को काफी नुकसान हुआ. 2 करोड़ रोजगार की बात तो दूर 15 लाख से भी ज्यादा नौकरियां गयी. यह कहना गलत नहीं होगा कि छोटे व्यापारियों, युवाओं खासकर बेरोजगारों में भाजपा विरोधी माहौल बनने का ये सबब बन गए. शहरों में भाजपा के वोट प्रतिशत में आयी कमी को इसी का नतीजा कह सकते हैं.

गौर करने वाली एक और बात यह है कि हिंदुत्व फासीवादियों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिशाना कोशिशों का बड़ा असर नहीं दिखा.

दलितों का अपमान व उनकी निर्मम हत्याएं भाजपा शासित राज्यों में चरम पर थी. हिंदुत्व कट्टरता का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों पर हमलें व उनकी हत्याओं के चलते भाजपा विरोधिता का बढ़ना स्वाभाविक था. इसी का नतीजा है कि राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ तीन राज्यों के विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल 78 सीटों में से 2013 के चुनावों में भाजपा ने 68 सीटें जीती थी जबकि हालिया चुनावों में उसने सिर्फ 31 सीटों तक सिमट गयी. यही हाल अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित सीटों का भी रहा.

मोदी के कैंपेन में नकारात्मक तत्वों की भरमार थी.

मोदी–शाह के भाषणों का आक्रामक तेवर ने जनता पर नकारात्मक असर ही छोड़ा. वोट बटोरने का मोदी करिश्मा घटता नजर आ रहा है.

भ्रष्टाचारी व घोटालेबाज – विजय रूपाणी, जय शाह, शौर्या डोभाल, जयंत सिन्हा, आरके सिन्हा, मुकुल राय, सुखराम, सुशील मोदी, रेड्डी ब्रदर्स, यदुरप्पा, शिवराज सिंह चौहान, रमण सिंह, अमित शाह समेत भाजपा शासित राज्यों के कई मंत्रियों व पार्टी नेताओं इत्यादि के बावजूद भाजपा स्वयं को ''ईमानदार पार्टी'' कहती रही और मोदी अपना जुमला ''न खाऊंगा, ना खाने दूंगा'' रटते रहे जिसकी असलियत को जनता ने बखूबी समझ लिया. अंबानी, अदानी एवं उन जैसों को रॉफेल जैसे सौदों के जरिए खिलाने की मोदी नीतियों का भंडाफोड़ लगातार हो ही रहा है.

आसाराम, गुरमीत राम–रहीम, राघवजी और सेक्स कांड में फंसे सैकड़ों बाबाओं और अम्माओं का साथ और आशीर्वाद का भंडाफोड़ होने के बावजूद भाजपा स्वयं को ''चरित्रवान पार्टी'' कहती है जिसे जनता ने चुनावों में ठुकरा दिया.

भाजपा के संघीय आतंकी संगठन, अजमेर ब्लास्ट के सजायाफता संघी, कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों के आतंकवादी घटना करते पकड़े जाने के बावजूद वह सबसे ''देशभक्त पार्टी'' होने का और आतंकवाद से लड़ने का ढोंग करती है जिसे जनता खासकर मुसलमान समझने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि सही विकल्प के अभाव में वे कांग्रेस या अन्य गैर–भाजपा दलों की शरण में जा रहे हैं.

सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाइवे व सड़क निर्माण, स्मार्ट सिटी, बुलेट रेल, आयुष्मान योजना, किसानों की आय दोगुनी करने रुर्बन सेंटर्स व ई–मंडियां आदि बुनियादी ढांचा के विकास जोकि देशी, विदेशी कारपोरेट घरानों का ही विकास है, पर जोर देते हुए, उसे ही ''सबका साथ, सबका विकास'' के रूप में दिखाने की कोशिश की गयी. इस ढोंग का जनता ने विधान सभा चुनावों में अपने तरीके से विरोध किया.

कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनाव नतीजें दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के कोरे वादों, सफेद झूठों, लफ्फाजी भरे जुमलों, नोटबंदी एवं जीएसटी जैसी जन विरोधी आर्थिक नीतियों तथा हिंदुत्व कट्टरपंथी भीड़ द्वारा की गयी 400 से ज्यादा निर्मम हत्याओं के खिलाफ अभिव्यक्त आम राय हैं.

छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव नतीजों का विश्लेषणः

सबसे पहले यहां यह गौर करने वाली बात है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने चुनाव आयोग के इस दावे कि छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव स्वेच्छापूर्वक, पारदर्शिता के साथ, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए गए हैं और यह गन तंत्र पर गणतंत्र की जीत है, को सिरे से खारिज किया है और यह स्पष्ट किया है कि दसियों हजार पुलिस व अर्ध सैनिक बलों की संगीनों के साए में संपन्न ये चुनाव गन तंत्र के जरिए गणतंत्र की मौजूदगी का झूठा एहसास दिलाने की कवायद मात्र हैं.

छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो यह साफ झलकता है कि राज्य में कांग्रेस ने दो–तिहाई बहुमत से भी ज्यादा 68 सीटें हासिल कर सरकार बनायी. कांग्रेस राज्य इकाई के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर 17 दिसंबर को पदभार ग्रहण किया. बाद में मंत्रि मंडल का गठन किया.

15 साल की सत्ता के बाद इस बार भाजपा 15 सीटों पर सिमट कर रह गयी. विधान सभा अध्यक्ष सहित रमण कैबिनेट के 12 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए. मंत्रियों के प्रति जनता की नाराजगी इससे साफ जाहिर होता है.

बस्तर संभाग के 12 में से सिर्फ 1 सीट–दंतेवाडा पर भाजपा को जीत मिली. जबकि सरगूजा संभाग में उसका खाता भी नहीं खुला. सभी 14 सीटों पर कांग्रेस ने फतह की. कांग्रेस ने राज्य की 10 एससी आरक्षित सीटों में से 6 जीती जबकि 29 एसटी आरक्षित सीटों में से 25 पर कब्जा जमाया. इससे यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं होगा कि भाजपा शासन से आदिवासी और दलित किस कदर खफा हैं.

इन चुनावों में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को 7 सीटें हासिल हुई जिनमें से जनता कांग्रेस को 5 और बसपा को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई. भाजपा के साथ जोगी की सांठगांठ के कांग्रेस प्रचार को नाकाम करने धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाने के बावजूद अजित जोगी दहाई का आंकड़ा छू नहीं सके.

भाजपा का यह आकलन कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बसपा गठबंधन एंटी इंकंबेंसी फैक्टर की काट साबित होगा, उलटा पड़ गया. इस गठबंधन से कांग्रेस की बजाए भाजपा को ही नुकसान हुआ. जोगी–रमण सिंह के बीच पिछले विधान सभा चुनावों के समय से ही किचड़ी पकती रही. पिछले चुनावों के एन वक्त पर अंतागढ़ से कांग्रेस अभ्यर्थी मंतु पवार की नाम वापसी, भाजपा प्रवेश, टेप कांड

आदि से इसका भंडाफोड़ हो जोने की वजह से जनता के बीच में भाजपा विरोधिता और बढ़ गयी.

छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया है कि ''रमण पर विश्वास, कमल संग विकास'' का नारा नाकाम साबित हुआ. भाजपा के जुमलों पर जनता का विश्वास नहीं रहा. भाजपा की वादाखिलाफी से जनता भली–भांति वाकिफ हो गयी.

राज्य में यह सत्ता परिवर्तन, विकास के नाम पर राज्य एवं देश की सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों को मिट्ठी के मोल देशी–विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने एवं किसानों, दलितों विशेषकर आदिवासियों को उनके जल–जंगल–जमीन से बेदखल करने का नतीजा है.

गोरक्षा, गोमांस पर पाबंदी, 'घर वापसी' सहित राज्य के दलितों, आदिवासियों एवं मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों जैसे अल्पसंख्यकों पर हिंदुत्व कट्टरपंथियों के लगातार हमलों का भी नतीजा हैं, ये चुनाव.

दसियों हजार किसानों की आत्महत्याओं एवं लाखों गरीब किसानों, खेत मजदूरों व आदिवासियों सहित बेरोजगारों के पलायन का सबब बनने वाली किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता ने इन चुनावों के माध्यम से अपना आक्रोश जताया था. कर्ज माफी, धान का समर्थन मूल्य लागत खर्च का डेढ़ गुना करने, बोनस देने व धान का दाना–दाना खरीदने के वादों को भाजपा ने भुलाया था.

विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्देषित जिन नीतियों के तहत लाखों सरकारी नौकरियों पर पाबंदी लगाकर बहुत कम मानदेय पर शिक्षाकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं सहित 54 सरकारी विभागों में अस्थायी, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी, उनके प्रति चुनावों के जरिए जनता ने जबर्दस्त विरोध प्रकट किया. आउट सोर्सिंग के नाम पर बाहरी लोगों को नौकरियां देने व बाहरी निजी संस्थाओं को नौकरियों में नियुक्ति का ठेका देने के प्रति रोष प्रकट करने का साधन बने थे, ये चुनाव.

सैकड़ों री–रोलिंग मिल, स्पंज आइरन उद्योगों को बंद करने तद्वारा 50 हजार से भी ज्यादा मजदूरों को रोजी–रोटी से वंचित करने वाली कॉरपोरेटपरस्त, सामंती हितैषी एवं मजदूर, किसान व मध्य वर्ग विरोधी नीतियों को जनता ने नकारा. ये नीतियां देशीय पूंजीपति विरोधी भी हैं.

संसाधनों की कारपोरेट लूट को सुनिश्चित करने के लिए व राज्य की आदिवासी जनता को विस्थापित करने के लिए जारी पाशविक प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक दमन योजना 'समाधान' जिसके तहत संचालित झूठी मुठभेड़ों, मुठभेड़ों, नरसंहारों, महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार, असीम अत्याचारों, हत्याओं, अवैध गिरफ्तारियों, लंबी कारावासी सजाओं, पूरे छत्तीसगढ विशेषकर बस्तर संभाग, राजनांदगांव व धमतरी, गरियाबंद जिलों को पुलिस छावनी बनाए जाने के खिलाफ जनमत का प्रदर्शन थे, ये नतीजें.

चुनाव नतीजें यह साफ कर रहे हैं कि सामाजिक एकता मंच, अग्नि जैसे प्रतिक्रांतिकारी संगठनों का गठन करवाकर जनपक्षधर पत्रकारों, आदिवासी हितैषी वकीलों, मानवाधिकार व सामाजिक संगठनों के नेताओं व कार्यकर्ताओं तक को डरा–धमकाकर, प्रताड़ित कर राज्य में जनवादी तरीके से काम न करने देने की फासीवादी नीतियों को जनता ने खारिज किया.

अपनी दलित विरोधी नीतियों को उजागर करते हुए आबादी के घटने का बहाना कर रमण सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 16 से 12 प्रतिशत घटाया था जिससे दलितों में गुस्सा फूट पड़ा. एससी, एसटी कानून में दलित व आदिवासी विरोधी संशोधन करते हुए दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा की दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया था. हालांकि बाद में केंद्र की मोदी सरकार ने मूल कानून को बरकरार रखते हुए अध्यादेश जारी किया था और कानून बनाया था.

राज्य के कांकेर जिले के परालकोट क्षेत्र में बसाए गए 133 गांवों की तीन लाख से भी ज्यादा बंगाली जनता खासकर बहुसंख्य दलितों की मांगों के संदर्भ में रमण सिंह ने यह टिप्पणी की कि छत्तीसगढ़ कोई धर्मशाला नहीं कि किसी को भी यहां बसाकर उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए. इससे स्वाभाविक तौर पर बंगाली आबादी कांग्रेस की ओर खींची चली आयी. आदिवासी–बंगाली अंतरविरोध को भुनाकर आदिवासी बहुल वोटों को हासिल करने के चक्कर में दिया गया उक्त बयान भी उलटवांसी साबित हुआ.

पूर्ण शराबबंदी को घोषणापत्र में शामिल करने वाले रमण सिंह सरकारी खजाना भरने के फेर में उसके ठीक विपरीत सरकारी शराब दुकानें खोलने की नीति अपनायी थी जिसे जनता ने सरकार का गर्दन मरोड़कर वापस लेने मजबूर किया. इससे जनता खासकर महिलाओं में भाजपा सरकार के प्रति अकथनीय गुस्सा बढ़ाया.

उपरोक्त प्रमुख वजहों से 35 लाख स्मार्ट फोन बांटने जैसी भाजपा की कई जनाकर्षक योजनाओं के बावजूद उन योजनाओं के भरोसे रही भाजपा को जनता ने राज्य विधान सभा चुनावों में हार का जबर्दस्त स्वाद चखाया.

चुनावों के काफी पहले से ही भाजपा, कांग्रेस और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के बीच जोड़–तोड़ चलता रहा. विगत के चुनावों के उलट इस बार भाजपा के 34

बागी प्रत्याशी मैदान में थे और उसके वोट काटने में सफल रहे जबकि कांग्रेसी जीत का स्वाद चखने एकजुट होकर चुनाव लड़े.

भाजपा की वादाखिलाफी का पर्दाफाश करते हुए जनता की ज्वलंत समस्याओं को लेकर लोकलुभावन वादों जैसे किसानों के लिए कर्ज माफी, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल, बिजली बिल आधा, पांच हार्स पावर के पंपों के लिए मुफ्त बिजली, सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने का कानून, बेरोजगारी भत्ता, एपीएल और बीपीएल परिवारों को हर माह 35 किलो चावल, पूर्ण शराबबंदी, अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 फीसदी से बढ़ाकर 16 फीसदी करना, राज्य में आउट सोर्सिंग पर पाबंदी लगाना आदि से युक्त घोषणापत्र के साथ जनता को बरगलाने में कांग्रेस इस बार सफल रही. क्योंकि चुनाव के काफी पहले से ही भाजपा सरकार की जनदमनकारी व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनपक्षधरता व जन आंदोलन का वह दिखावा करती रही.

यह सर्वविदित है कि कांग्रेस, भाजपा दोनों ही शोषक–शासक वर्गीय पार्टियां हैं, उनके ही हित में काम करने वाली हैं और जनविरोधी हैं.

भाजपा की केंद्र, राज्य सरकारें अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की ही जनविरोधी व साम्राज्यवादपरस्त एलपीजी नीतियों पर अभूतपूर्व आक्रामकता व तेजी के साथ अमल करती रहीं और कर रही हैं. हमारी पार्टी व क्रांतिकारी आंदोलन को 2022 तक खत्म करने की 'समाधान' दमन योजना पर अमल कर रही हैं. छत्तीसगढ़ में चुनावों के दौरान भी गांवों पर सशस्त्र बलों के हमलें नहीं रुके. माओवादियों के दमन में चुनाव आचार संहिता आड़े नहीं आयी और उल्टे लाखों अतिरिक्त सशस्त्र बलों को तैनाती के साथ दमन में इजाफा करके चुनावी प्रहसन को पूरा किया गया था. राज्य में सत्ता से बेदखल भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों में राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कवायद शुरू की है. देश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने की योजना के तहत भाजपा की यह कवायद जारी रहेगी.

कांग्रेस जोकि तथाकथित आजादी या सत्ता हस्तांतरण के बाद से सबसे ज्यादा समय तक देश और राज्यों में सत्तारूढ़ रही, जनविरोधी नीतियों पर अमल करने में, कश्मीर सहित उत्तर–पूर्वी राष्ट्रीयताओं के आंदोलनों एवं क्रांतिकारी आंदोलन को खून की नदी में डुबाने में माहिर है. तेलंगाना, नक्सलबाड़ी सहित दंडकारण्य, बिहार–झारखंड एवं देश भर के अन्य क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में पाशविक दमन को जारी रखने का इतिहास रहा है, कांग्रेस का. कांग्रेस ने ही माओवादियों को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा घोषित किया था. छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ को सबसे पहले 2003 में कांग्रेस ने ही भेजा था. सलवा जुडुम का भरपूर समर्थन किया था, देश भर में ऑपरेशन ग्रीनहंट को उसी ने शुरू किया था. कांग्रेस व भाजपा के इस दमनकारी इतिहास व चरित्र को हमेशा मद्देनजर रखकर जनता को इनके प्रति सतर्क व सावधान रहना चाहिए और अपने जायज अधिकारों के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए.

कांग्रेस की नयी सरकार के गठन के संदर्भ में जनता को चाहिए कि वह संसाधनों की बेरोकटोक लूट को बंद करने के लिए देशी–विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों के साथ किए गए तमाम एमओयु रद्द करने, संपूर्ण कर्ज माफी के अलावा धान सहित तमाम अनाजों, दलहन–तिलहनों व वनोपजों के समर्थन मूल्य को दोगुनी करने समेत किसानों की सभी मांगें पूरी करने, जेलों में बंद आदिवासी, गैर आदिवासी जनता को निशर्त रिहा करने, डीआरजी, बस्तरिया बटालियन, आदिवासी बटालियन, ब्लैक पैंथर्स आदि विशेष कमांडो बलों को रद्द करने, अर्ध–सैनिक बलों सहित तमाम अतिरिक्त सशस्त्र बलों को वापस भेजने व दमन योजना 'समाधान' को बंद करके जनवादी–प्रगतिशील व मानवाधिकार संगठनों को स्वेच्छा से काम करने के जनवादी माहौल एवं जनवादी अधिकारों को बहाल करने, आउट सोर्सिंग बंद करके तमाम विभागों में खाली पड़े पदों पर अविलंब स्थायी नियुक्तियां करने तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र के तमाम वादों को तुरंत पूरा करने की मांगों के साथ जन आंदोलनों को तेज करें.

शिक्षाकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं सहित तमाम सरकारी विभागों के संविदा, दैनिक वेतनभोगी, केजुअल कर्मचारियों की नियुक्तियों को स्थायी बनाकर तमाम वेतन भत्तों को तत्काल प्रभाव से लागू करने तमाम कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़नी चाहिए. बैलाडीला से कच्चा माल व सस्ती बिजली उपलब्ध कराकर बंद पड़े स्पंज आइरन व री–रोलिंग मिलों को चालू करवाकर स्थायी नियुक्तियों के साथ मजदूरों को रोजी–रोटी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर तमाम छंटनीशुदा मजदूरों को सड़क पर उतरना चाहिए. कानूनी, गैर–कानूनी व खुला, गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करते हुए संगठित, व्यापक व जुझारू जन आंदोलनों का निर्माण करने की दिशा में सभी को कदम बढ़ाना चाहिए. जन आंदोलनों व जन प्रतिरोध के साथ–साथ भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध के साथ इन तमाम आंदोलनों को जुड़ना चाहिए.

❍

विधानसभा के चुनाव बहिष्कार के आह्वान को सफल बनाने वाली क्रांतिकारी जनता को लाल सलाम!

दक्षिण बस्तर डिविजन

डिविजन में चुनाव बहिष्कार कार्यक्रम का संचालन व्यापक रूप में हुआ. इस मौके पर एसजडसी की ओर से जारी सर्कुलर, पर्चा और पोस्टर आदि प्रचार सामग्री को जनता में ले जाया गया. इसके पहले जन संगठनों व आरपीसी के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक तौर पर मोटिवेट किया गया. छात्र–छात्राओं, कर्मचारियों में भी अच्छी तरह प्रचार किया गया. बुकलेट, पर्चा आदि बांटे गए. कई प्रचार टीमें बनाई गईं जिनके द्वारा गांव–गांव में बैठकों, सभाओं और सम्मेलनों का आयोजन हुआ. कोंडापल्ली हाट बाजार में भी आमसभा का आयोजन हुआ. दीवाल लेखन, पोस्टरों और बैनरों के साथ विस्तृत रूप से प्रचार किया गया. कई जन समस्याओं पर आयोजित आम सभाओं के जरिए भी जनता में राजनीतिक प्रचार किया गया.

चुनाव बहष्कार के नारे लगाती जनता

इस दौरान बड़े सेट्टी एलओएस में गांव स्तर की 10 आम सभाओं का आयोजन हुआ, जिनमें शामिल हुए थे, 910 महिलाएं और 1009 पुरुष. दोरनापाल एलओएस एरिया में गांव स्तर की 10 सभाओं का आयोजन हुआ, जिनमें 213 महिलाएं और 199 पुरुष शामिल हुए. गोंदपल्ली में की गई पंचायत स्तर की सभा में 166 महिलाएं और 120 पुरुष शामिल हुए. मूलेर पंचायत स्तर की सभा में 61 महिलाएं और 81 पुरुष शामिल हुए. गोंगे पंचायत स्तर की सभा में 160 महिलाओं और 170 पुरुषों ने हिस्सा लिया.

चुनाव बहिष्कार के दौरान संचालित प्रतिरोध में हजारों जनता व मिलिशिया शामिल हुईं. इसमें महिलाएं–2,133, पुरुष–12,964 थे. इन सभी ने मिल कर हजारों स्पाइक होल्स बनाए.

इस राजनीतिक प्रचार व सैनिक प्रतिरोध के फलस्वरूप केरलापाल एरिया के कोड्रे, बड़े शेट्टी, बेज्जि पंचायत को छोड़ और कहीं भी मतदान नहीं हुआ.

चुनाव बहिष्कार के दौरान संचालित सैनिक कार्यवाहियों में कुल मिलाकर पुलिस के 11 जवान मारे गए और 72 जवान घायल हुए. इनमें से मिलिशिया द्वारा लगाए गए बूबीट्राप विस्फोट होकर एक जवान मारा गया और चार लोग घायल हुए. स्पाइक होल्स में गिरने की वजह से पुलिस के 52 जवान घायल हुए.

एक इंसास एलएमजी, कारतूस सहित दो एके मैगजीन के अलावा और कुछ सामग्री पीएलजीए द्वारा जब्त की गई.

पश्चिम बस्तर डिविजन

गंगालूर एरिया

एरिया में तीनों जनसंगठनों – डीएकेएमएस, केएएमएस व सीएनएम और क्रांतिकारी जनताना सरकारों ने मिल कर चुनाव बहिष्कार अभियान का संचालन किया. इसके तहत एसजेडसी से आए सर्कुलर, अपील, पल्टा घोषणा पत्र के बारे में सभी कार्यकर्ताओं और कैड़रों को क्लास के रूप में समझाया गया. 7 टीमों, जिनमें से प्रत्येक में 30 लोग शामिल थे, ने पूरे एरिया में प्रचार किया. चुनाव बहिष्कार के तहत दो एरियाओं के दायरे में सीएनएम के एक वर्कशाप का संचालन भी हुआ, जिसमें 9 गानें और 2 नाटक बनाए गए. पोस्टरों, बैनरों के साथ विस्तृत रूप से प्रचार किया गया. दीवाल लेखन के लिए 7 टीमें बनायी गईं. हर टीम में 15 लोग शामिल थे. चुनाव बहिष्कार अभियान के पहले चरण में गांव स्तर की 62 आमसभाओं का आयोजन हुआ. इन सभाओं में 2280 महिलाओं और 3371 पुरुषों ने भाग लिया. दूसरे चरण में पंचायत स्तर की 17 आम सभाओं का आयोजन हुआ, जिनमें 2305 महिलाओं और 3705 पुरुषों ने शिरकत की. तीसरे चरण में 6 सभाएं आयोजित की गईं, जिनमें 5663 पुरुषों एवं 3777 महिलाओं ने हिस्सा लिया. इनके अलावा सरपंचों, मुखियाओं और बुजुर्गों की बैठकें भी की गई जिनमें 222 महिलाएं और 254 पुरुष शामिल हुए.

इन सभाओं के जरिए ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भाजपा की रमनसिंह सरकार के 15 वर्ष के कार्यकाल में जारी बर्बर दमन, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के ऊपर किए गए हमलों, विस्थापन, बेरोजगारी, महंगाई के अलावा सरकार की जनविरोधी नीतियों के बारे में जनता को अवगत कराया गया. उन गांवों, जहां पुलिस कैंप मौजूद हैं, में भी प्रचार किया गया.

उपरोक्त राजनीतिक अभियान के अलावा चुनाव बहिष्कार को विफल करने के दुश्मन की योजना के मद्देनजर सैनिक अभियान का संचालन भी हुआ. इसमें पीएलजीए के प्रथम व द्वितीय बलों के अलावा बड़े पैमाने पर मिलिशिया और जनता ने भाग लिया. मिलिशिया और

जनता ने 8 हजार स्पाइक होल्स बनाए. उनकी खुदाई में 1078 महिलाएं और 5012 पुरुष शामिल हुए. 155 बूबीट्रैप की टीमें, 26 क्लेमोर टीमें, 17 तोप टीमें और 46 तीर–धनुष टीमें भी प्रतिरोध में शामिल हुईं. पूरे एरिया में प्रतिरोध के इतने जबर्दस्त इंतजामात किए गए कि पुलिस के दो जवान स्पाइक होल्स में गिर कर घायल होने के बाद पुलिस बलों ने एरिया में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पायी. नतीजतन गंगालूर एरिया में मौजूद 19 पंचायतों के 60 गांवों में संपूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार हुआ. लुटेरी सरकार के एक लाख 50 हजार सशस्त्र बल जनता से वोट डलवाने में पूरी तरह हार गए.

चुनाव बहिष्कार आह्वान को जनता में ले जाने के लिए जोन सीएनएम द्वारा बनाए गए वीडियों गीतों की एक झलक

भैरमगढ़ एरिया

एरिया में चुनाव बहिष्कार प्रचार एक महीने पहले से शुरू हुआ. एसजेडसी से आए सर्कुलर, पर्चा आदि के निचोड़ को व्यापक जनता में पहुंचाने के लिए पहले राजनीतिक कक्षाओं का आयोजन हुआ. बाद में तीनों जन संगठनों और जनताना सरकारों ने सभा, रैली, पोस्टर, बैनर, दीवाल लेखन, भाषण, नारा, गाना और नाटक आदि के जरिए एसजेडसी के चुनाव बहिष्कार आह्वान को गहराई से जनता तक पहुंचाया. 4500 पर्चों, 3000 पोस्टरों और 180 बैनरों के साथ प्रचार किया गया.

एरिया में गांव स्तर की 90 आम सभाएं आयोजित हुईं. इनमें 7515 महिलाएं और 8090 पुरुष, कुल मिलाकर 16,005 लोग शामिल हुए थे. पंचायत स्तर की 16 बैठकें हुईं, जिनमें 3500 महिलाओं और 6700 पुरुषों, कुल मिलाकर 10,200 लोगों की भागीदारी थी. पांच एरिया स्तर की सभाएं संपन्न हुई थीं, जिनमें 3090 महिलाओं और 4548 पुरुषों कुल मिलाकर 7638 लोगों ने भाग लिया. गांवों में मौजूद संसदीय पार्टियों के छोटे–मोटे नेताओं, सरपंच, सचिव, पटेल, मुखियाओं आदि लोगों की बैठक करके उन्हें चुनाव बहिष्कार आह्वान के बारे में समझा दिया गया. दो जगहों पर की गईं इन बैठकों में 18 महिलाएं और 120 पुरुष शामिल हुए. 118 महिला और 292 पुरुष वड्डे/पूजारी लोगों के साथ भी बैठकें हुईं.

प्रतिरोध की बात करें, तो मिलिशिया द्वारा 7128 स्पाइक होल्स बनाए गए.

इस चुनाव बहिष्कार प्रचार अभियान व प्रतिरोध के चलते जहां आरपीसी मौजूद है, वहां मतदान बिलकुल ही नहीं हुआ. भैरमगढ़ एरिया के डेढ़ सौ गांवों में से 90 गांवों में एक भी वोट नहीं डाला गया. जबकि 60 गांवों में कुछ हद तक मतदान हुआ.

मद्देड एरिया

एरिया में एक महीने पहले से ही चुनाव बहिष्कार का प्रचार अभियान शुरू हुआ. गांवों की जनता के अलावा शिक्षाकर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, छात्र–छात्राओं के बीच में 500 पर्चों, 3000 पोस्टरों, 24 बैनरों के साथ प्रचार किया गया. इस दौरान गांव स्तर की 18 सभाओं का आयोजन किया गया. इनमें 1500 महिलाओं और 2500 पुरुषों ने हिस्सा लिया. 494 स्पाइक होल्स की खुदाई भी की गई.

चुनाव कराने के लिए आनेवाले सरकारी सशस्त्र बल जब वापस जा रहे थे, 14 नवंबर को पीएलजीए द्वारा ट्रक को उड़ा दिया गया, तो बीएसएफ के चार जवान, डीआरजी का एक जवान और गाड़ी चालक घायल हो गए.

दरभा डिविजन

डिविजन में चुनाव बहिष्कार प्रचार अभियान के पहले सीएनएम के डिविजन स्तर की कार्यशाला का आयोजन हुआ था. इसमें चुनाव बहिष्कार संबंधित कई कला रूपों को तैयार करके जनता में ले जाया गया. कला रूपों के अलावा पर्चों, पोस्टरों, बैनरों, दीवाल लेखन के जरिए प्रचार किया गया. क्रांतिकारी जनताना सरकारों के वैकल्पिक कार्यक्रम से भी जनता को अवगत कराया गया.

क्रांतिकारी जनता ने चुनाव प्रचार के लिए कहीं भी भाजपा वालों को कदम नहीं रखने दिया. जबकि विभिन्न विपक्षीय पार्टियों के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर डिविजन में जारी गैर–कानूनी गिरफ्तारियों, लूट व अत्याचारों के बारे में जवाब–तलब किया. अपनी न्यूनतम जरूरतों के बारे में भी सवाल किया.

मलिंगेर एरिया में चुनाव बहिष्कार के तहत एक बड़ी आम सभा का आयोजन हुआ. इसमें 3000 लोगों ने शिरकत की. पत्रकारों ने भी शामिल होकर इस सभा को अखबरों में कव्हर किया.

सरपंचों, गांवों के मुखियाओं, पूजारियों की भी बैठक करके चुनाव में नहीं भाग लेने की समझाइश दी गयी. चुनाव बहिष्कार के इस अभियान के चलते अंदरूनी गांवों में जनता ने वोट नहीं डाला.

निर्वाचन के लिए आने वाले पुलिस बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से डिविजन में 4000 से अधिक स्पाइक होल्स बनाए गए. इनमें गिर कर लगभग पुलिस के 15

दुश्मन की निरंतर गश्त के दरमियान ही जोन भर में चुनाव बहिष्कार का जबर्दस्त प्रचार

जवान घायल हुए. दो मुखबिर भी इनमें गिर कर घायल हुए. इसकी वजह से दुश्मन विगत की तरह आक्रामक रूप से ऑपरेशन्स नहीं कर पाया. एक जगह पर पीएलजीए द्वारा विस्फोट किए गए बूबीट्राप की चपेट में आकर पुलिस के 5 जवान घायल हुए.

उत्तर बस्तर डिविजन

रावघाट एरिया

रावघाट एरिया में गांव–गांव में जन सभाओं को संचालित कर हर वर्ग की जनता से अपील की गई कि वे झूठे विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करें. इस दौरान लगभग 300 पोस्टरें चस्पा किए गए. 766 पर्चे बांटे गए. सड़कों एवं साप्ताहिक बाजारों में 270 बैनर बांधे गए. विभिन्न गांवों के 60 से 70 प्रमुख लोगों से चुनाव बहिष्कार के बारे में बातचीत की गई. प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई. कुछ ही लोगों को छोड़ कर एरिया के सभी पंचायतों की जनता ने सक्रिय रूप से चुनाव का बहिष्कार किया. चुनाव बहिष्कार के तहत एरिया में पीएलजीए का प्रतिरोध भी सफल हुआ.

कुव्वे एरिया

चुनाव बहिष्कार के आह्वान को एरिया की जनता तक पर्चों, पोस्टरों और पत्रों के माध्यम से पहुंचाया गया. इस दौरान 1600 पर्चे बांटे गए. सड़कों पर भी पर्चों व पोस्टरों द्वारा प्रचार किया गया. नतीजतन एरिया की अधिकांश जनता ने चुनावों का बहिष्कार किया. एरिया के 3–4 पंचायतों में सरपंचों, सचिवों के अलावा पारंपरिक मुखियाओं के बीच भाजपा ने पैसे बांटे. इसके बावजूद जनता ने चुनावों का बहिष्कार किया.

प्रतापुर एरिया

चुनाव बहिष्कार के तहत एरिया में पोस्टरों, बैनरों, दीवल लेखन व पर्चों के साथ व्यापक रूप से प्रचार किया गया. इस दौरान एसजेडसी द्वारा जारी सर्कुलर और जोन जनताना सरकार तैयारी कमेटी द्वारा जारी पल्टा घोषणा पत्र के बारे में गहराई से समझाने के लिए चार जगहों पर गांवों के पार्टी निर्माणों को दो–दो दिनों तक राजनीतिक कक्षाओं का आयोजन किया गया. कुछ गांवों के मुखियाओं के साथ बातचीत करके चुनाव बहिष्कार के बारे में अवगत कराया गया. इन सारे प्रयासों के फलस्वरूप एरिया के एक–दो गांवों को छोड़ कर बाकी सभी गांवों की जनता ने चुनावों का बहिष्कार किया.

चुनाव के दौरान मिलिशिया का मोटिवेशन करके उसे प्रतिरोध में शामिल किया गया.

माड डिविजन

कुतुल एरिया

तीन जन संगठनों, जनताना सरकारों, पीएलजीए और पार्टी द्वारा पर्चों, पोस्टरों, बैनरों और दीवाल लेखन के जरिए एरिया में व्यापक रूप से चुनाव बहिष्कार का प्रचार किया गया. गांव स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जनता की आमसभाओं को आयोजित करके चुनाव बहिष्कार के बारे में जनता को अवगत कराया गया. इनके अलावा ग्रामसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें 4 जनताना सरकारों के दायरे की जनता ने भाग लिया. ग्राम सभा में चुनाव बहिष्कार और पुलिस कैंप के विरोध में चर्चा की गई. 401 महिलाएं, 654 पुरुष इसमें शामिल हुए.

दो जगहों पर गांव के मुखियाओं की बैठक कर चुनाव बहिष्कार के बारे में चर्चा की गई. 110 मुखिया इन बैठकों में शामिल हुए. इस व्यापक प्रचार के चलते एरिया के 103 गांवों में एक भी वोट नहीं डाला गया. पुलिस कैंपों के नजदीक के 36 गांवों में डरा–धमका कर पुलिस ने जबरन मतदान करवाया.

नेलनार एरिया

तीन जन संगठनों, जनताना सरकारों, पीएलजीए और पार्टी द्वारा पर्चों, पोस्टरों, बैनरों और दीवाल लेखन के जरिए एरिया में व्यापक रूप से चुनाव बहिष्कार का प्रचार किया गया. गांव से लेकर पंचायत स्तर तक ग्राम सभाओं का आयोजन करके चुनाव बहिष्कार पर चर्चा की गई. इस प्रयास के फलस्वरूप 35 गांवों की जनता ने संपूर्ण रूप से चुनावों का बहिष्कार किया. पुलिस कैंपों के इर्द–गिर्द के गांवों में जनता को डरा–धमकाकर, लालच के आलावा कई तरह की हरकतें करके मतदान करवाया गया. एक उदाहरण लें, तो मंडेली सरपंच को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर गांव वालों को उसे छुड़ा कर ले जाने के लिए थाने में आने की खबर दी. जब अपने सरपंच को छुड़ाने लोग गए, तो पुलिस ने कहा कि वोट डालने से वे सरपंच को छोड़ेंगे. नहीं, तो मार देंगे. ऐसी कई घटनाएं घटी थीं. जिनकी वजह से कुछ गांवों में कुछ हद तक मतदान हुआ.

पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ 2 से 8 दिसंबर तक क्रांतिकारी उत्साह और जोश के साथ मनी!

प्रिय पाठकों!

(आपको यह सूचित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष में भी भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) द्वारा दिए गए आह्वान का पालन करते हुए दंडकारण्य के गांव-गांव में जन मुक्ति छापामार सेना-पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ पूरे जोश-खरोश के साथ मनायी गयी. इस मौके पर सीएमसी द्वारा तमाम पार्टी कतारों व जनता के लिए अलग-अलग संदेश जारी किए गए. अपने संदेशों के जरिए सीएमसी ने देश की उत्पीड़ित जनता एवं पार्टी, पीएलजीए, संयुक्त मोर्चा की सभी पार्टी कतारों समेत पीएलजीए के सभी स्तरों के लाल कमांडरों व लाल योद्धाओं का आह्वान किया कि वे देशभर में साम्राज्यवाद-विरोधी, सामंतवाद-विरोधी वर्ग संघर्ष को तेज करें, जनाधार को बढ़ाते हुए, पार्टी और पीएलजीए को मजबूत करते हुए गुरिल्ला युद्ध को व्यापक और तेज करें, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के उन्मूलन के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' रणनीतिक हमले को हराएं.

दंडकारण्य भर में पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ के मौके पर विभिन्न स्तरों – गांव, पंचायत, दो-तीन जनताना सरकारों के दायरे में, एरिया स्तर पर आयोजित सभाओं, रैलियों में पर्चा, पोस्टर, पुस्तिका, बैनर आदि के जरिए सीएमसी संदेश को व्यापक पैमाने पर कैडरों व जनता तक पहुंचाया गया. जोन भर से इन आयोजनों से संबंधित रिपोर्टों का आना जारी है. प्रभात के आगामी अंक यानी जनवरी-मार्च, 2019 में पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ के आयोजनों से संबंधित ग्राउंड रिपोर्ट्स प्रकाशित करेंगे. अभी यहां हम पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्पीड़ित जनता के लिए सेंट्रल मिलिटरी कमीशन (सीएमसी), भाकपा (माओवादी) द्वारा जारी संदेश के मुख्य अंश दे रहे हैं.

– संपादक मंडल)

ये हैं पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ पर जारी सीएमसी संदेश के मुख्य अंश

सर्वविदित है कि हमारी पार्टी के संस्थापक, शिक्षक, भारतीय क्रांति के निर्माता, अमर शहीद कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी के दिशानिर्देशन में, अमर शहीद कामरेड्स श्याम, महेश और मुरली की प्रेरणा से, हजारों अमर शहीदों की स्फूर्ति से 2 दिसम्बर, 2000 को हमारी पीएलजीए का गठन हुआ. पीएलजीए की इस 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर समूची पार्टी कमेटियों, कमानों, पार्टी सदस्यों, पीएलजीए के कमांडरों, योद्धाओं, क्रांतिकारी जन सरकारों, जनसंगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं, जनमिलिशिया के सभी सदस्यों और क्रांतिकारी जनता को सेंट्रल मिलिटरी कमीशन (सीएमसी) भाकपा (माओवादी) ने क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ लाल सलाम् पेश किया है. 'समाधान' हमले को हराने के लिए साहसिक हमलों को अंजाम देने के क्रम में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर योद्धाओं को, कई मुठभेड़ों, फर्जी मुठभेड़ो, धोखेबाजीपूर्ण हमलों व दुर्घटनाओं में एवं जेलों में, अस्वस्थता की वजह से और अन्यान्य कारणों से अपनी जानें न्योछावर करने वाले सभी अमर शहीदों को विनम्रतापूर्वक क्रांतिकारी जोहार अर्पित करते हुए उनके द्वारा पालन किए गए कम्युनिस्ट जीवन के मूल्यों, दुश्मन के सामने न झुकने वाले उनके साहस, क्रांति की जीत पर उनके अटल विश्वास, उनके अथक लड़ाकू प्रयास, जनता के प्रति उनके समर्पण को आदर्श के रूप में लेकर लागू करने का आह्वान किया. उनके लक्ष्य को हासिल करने और उनके सपनों को साकार करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ने की शपथ लेने कहा.

सीएमसी ने यह आशा व्यक्त किया है कि देशभर में चलायी गयी गुरिल्ला युद्ध कार्रवाइयों में घायल हुए सभी कामरेड शीघ्र ठीक होकर लड़ाकू जोश के साथ फिर से युद्ध के मैदान में कूद पड़ेंगे.

पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर दुश्मन द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' रणनीतिक हमले को हराने के लक्ष्य से पीएलजीए को संगठित करने हेतु देशभर में दिसंबर महीने में भर्ती अभियान चलाने का आह्वान भी सीएमसी की ओर से दिया गया जिस पर दंडकारण्य जोन में अमल किया गया.

भारत की नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने और एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस द्वारा निर्देशित कर्तव्यों को हासिल करने के लिए समर्पित होकर, अथक प्रयास करते हुए 'समाधान' हमले को हराने के लिए लड़ते हुए इस साल (दिसंबर 2017 से नवंबर 2018 तक) देशभर में सर्वहारा के लगभग 235 उत्तम पुत्र–पुत्रिकाएं शहीद हुई. इनमें सीआरबी के मातहत काम करने वाले विभिन्न पार्टी और पीएलजीए यूनिटों के 13 कामरेड्स, दण्डकारण्य (डीके) के 168 कामरेड, बिहार–झारखण्ड (बीजे) के 18 कामरेड, आंध्रा, ओड़िशा सीमा (एओबी) इलाके के 12 कामरेड, ओड़िशा के 10 कामरेड, तेलंगाना के चार कामरेड, महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश –छत्तीसगढ़ (एमएमसी) के 9 कामरेड, आंध्रप्रदेश के एक कामरेड इस अवधि में शहीद हुए. इनमें से 75 से अधिक महिला कामरेड शामिल हैं.

कामरेड श्याम कामरेड महेश कामरेड मुरली

इस अवधि में केंद्रीय कमेटी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड देवकुमार सिंह (अरविंद, सुजीत दा), सीआरबी स्टाफ कामरेड दण्डबोइना स्वामी (प्रभाकर, सीआरबी प्रेस, डीवीसी स्तर), डीके के गढ़चिरोली में डीवीसी सचिव राउतु विजेंदर (श्रीनू) डीवीसी सदस्य कामरेड्स वासुदेव आत्रम (नंदू, विक्रम), डोलेश आत्रम (साईनाथ), ओड़िशा के कंधमाल–कलाहण्डी–बौध–नुवापाड़ा (केकेबीएन) डिविजन कमेटी के सदस्य कामरेड्स शंकर मांझी (डेविड, विनय), लक्कू कोर्राम (मदन), एओबी के मलकानगिरी डीवीसी के सचिवालय सदस्य कामरेड वलिगोण्डा प्रमीला (शारदा, जिलानी बेगम, मीना), बीजे के लातेहार जिले में दो सबजोनल कमांडरों कामरेड्स शिवलाल और श्रवण कुमार, डीके के गढ़चिरोली में एक एरिया कमेटी सचिव, एमएमसी में दरेकसा एरिया कमेटी सचिव, ओड़िशा में गोबरा एरिया कमेटी सचिव, एसी/पीपीसी सदस्य डीके के 33 कामरेड्स, एओबी के दो कामरेड्स, एमएमसी के दो कामरेड्स, ओड़िशा के एक कामरेड, तेलंगाना के दो कामरेड, पार्टी व पीएलजीए सदस्य डीके के 56 कामरेड, बीजे के 16 कामरेड, एओबी के 8 कामरेड, एमएमसी के चार कामरेड, ओड़िशा के चार कामरेड, तेलंगाना के तीन कामरेड, डीके के आरपीसी नेता 9 कामरेड, जनसंगठन के नेता व कार्यकर्ता 7 कामरेड, मिलिशिया कमांडर व सदस्य 35 कामरेड, क्रांतिकारी जनता 8 कामरेड, एओबी के एक मिलिशिया के अलावा अलग–अलग राज्यों में कई जननेता और क्रांति के समर्थक इस अवधि में शहीद हुए.

प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' को हराने के लिए देशभर में हमारे द्वारा किए गए राजनीतिक, सैनिक और सांगठनिक कार्य–उनके परिणाम :

दिसंबर 2017 से नवंबर 2018 तक हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए द्वारा विभिन्न स्तरों में जारी गुरिल्ला युद्ध–जनयुद्ध में विभिन्न गुरिल्ला जोनों और लालप्रतिरोध इलाकों में लगभग 300 गुरिल्ला कार्रवाइयों को अंजाम दिया. पीएलजीए द्वारा सीधा दुश्मन के बलों पर लगभग 180 कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया. इनमें 7 बड़ी कार्रवाइयां शामिल है, वे हैं – बुढ़ा पहाड़ (गढ़वा, बीजे), डीके के इरपानार एम्बुश (नारायणपुर), एलाड़मड़गु एम्बुश (सुकमा), कासारम–पालोड़ एम्बुश (सुकमा), तुमला एम्बुश (बीजापुर), चोलनार एम्बुश (दंतेवाड़ा), मुर्दोण्डा (बीजापुर) के पास माइनप्रूफ गाड़ी (एमपीवी) पर एम्बुश शामिल हैं. इसी तरह 21 मध्यम किस्म की कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया. दुश्मन पर किए गए कार्रवाइयों में लगभग 90 पुलिस जवान मारे गए और 190 घायल हो गए. डीके में जन मिलिशया द्वारा अंजाम दिए गए स्पाइक होल (कांटा–युक्त गड्ढे) युद्धतंत्र में इस साल 100 जवान घायल हो गए. जबकि दुश्मन बलों से पीएलजीए बलों ने विभिन्न किस्म के 25–30 हथियार, हजारों कारतूस और अन्य सामग्री को जब्त किया. इस एक साल की अवधि में लगभग 85 कार्रवाइयों में 106 जन दुश्मनों, मुखबिरों, लुटेरे राजनेताओं और प्रतिक्रियावादी तत्वों का सफाया किया.

छत्तीसगढ़ में चुनाव बहिष्कार के दौरान संचालित राजनीतिक–सैनिक अभियान के तहत सिलसिलेवार एम्बुश की घटनाएं हुई. इस अभियान के तहत जारी राजनीतिक प्रचार और गुरिल्ला युद्ध कार्रवाइयों द्वारा संसदीय व्यवस्था के विकल्प के रूप में जन राजसत्ता के अंगों का निर्माण करने का राजनीतिक संदेश न सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता बल्कि पूरे देश की जनता के पास पहुंचाया गया.

पार्टी योजनाबद्ध ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन को नये इलाकों में विस्तारित कर रही है. दुश्मन के दलालों, कई मुखबिर–कोवर्ट नेटवर्कों को पीएलजीए और जनता द्वारा उन्मूलन किया जा रहा है. ग्रामीण इलाकों में जमीन समस्या को केंद्र में रखकर वर्ग संघर्ष को तेज करने का प्रयास कर रहे हैं. क्रांतिकारी जन राजसत्ता के अंगों का निर्माण और उन्हें विकसित करते हुए क्रांतिकारी भूमि सुधारों को लागू

किया जा रहा है. जनता के जीवन स्तर बढ़ाने के लिए भूमि समतलीकरण अभियानों और उत्पादन को बढ़ाने के अभियानों में जनता को शामिल किया जा रहा है.

जनता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और रोजमर्रा की समस्याओं पर, विशेषकर, जल, जंगल, जमीन, इज्जत, अधिकार के लिए, विस्थापन के विरोध में, राज्यहिंसा के खिलाफ कई आंदोलनों का निर्माण करते हुए जनाधार को बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं. झारखण्ड में सीएनटी और एसपीटी कानूनों में, भूमि अधिग्रहण कानून–2013 में सुधारों के खिलाफ कई जनांदोलन संचालित किए गए हैं. तेलंगाना राज्य स्थापित होने के बावजूद, जनता की मौलिक समस्याओं और दैनिक समस्याओं का हल नहीं हुआ, इसे जनता के सामने स्पष्ट करने के साथ–साथ जनवादी तेलंगाना के लिए लोगों को राजनीतिक रूप से गोलबंद करते हुए, जनांदोलन निर्माण कर रहे हैं. ट्राइ–जंक्शन इलाके में जनता की राजनीतिक, आर्थिक और दैनिक समस्याओं को लेकर जनआंदोलनों के जरिए वहां क्रमशः हमारी जड़ें मजबूत कर रहे हैं. पार्टी और पीएलजीए का बोल्शेवीकरण और संगठितीकरण करने के लिए कुछ इलाकों में शिक्षा कार्यक्रमों और शुद्धीकरण कार्यक्रमों को संचालित किए हैं और कुछ इलाकों में जारी रखे हुए हैं. पिछले 4–5 सालों में सीआरबी के इलाके में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम (एलटीपी) और मिलिटरी क्षेत्र के लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को संचालित किया गया है. यथासंभव कुछ जगहों पर क्रांतिकारी जनसंगठनों और जन राजसत्ता के अंगों (आरपीसी) के अधिवेशनों को नीचे से लेकर ऊपर तक संचालित कर उनके नेतृत्व को मजबूत किया जा रहा है. जनसंगठनों के निर्माणों को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं.

शहरी इलाकों में जहां हमारी शक्तियां मौजूद हैं, व्यापक छात्र, मजदूर और महिला क्षेत्रों में आंदोलनों का निर्माण कर रहे हैं. क्रांतिकारी आंदोलन का पूरी तरह सफाया करने के लक्ष्य से किराये के सरकारी बल और उनके हत्यारे खुफिया गिरोहों द्वारा जारी राज्यहिंसा के खिलाफ मानवाधिकार आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं. 'नया भारत' के निर्माण के नाम पर देश में 'हिंदू राज्य' की स्थापना के लक्ष्य से धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, प्रगतिशील और जनवादी ताकतों पर हिंदू फासीवादी शक्तियों के हमलों के खिलाफ व्यापक जनांदोलनों का निर्माण कर रहे हैं. विभिन्न राजनीतिक विषयों पर क्रांतिकारी प्रचार कार्यक्रमों को संचालित करते हुए, क्रांतिकारी शक्तियों में क्रांतिकारी जोश भरने का प्रयास कर रहे हैं.

प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' को हराने के लिए जारी हमारे प्रयासों की वजह से हमें एक–एक राज्य/इलाके में एक–एक तरह के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है. इन सकारात्मक परिणामों को यदि हम समूचे देश में विस्तारित करते हैं तो अवश्य प्रतिकूलताओं के स्थान पर प्रधान रूप से अनुकूलताओं को पैदा कर सकते हैं. ये अनुकूलताएं 'समाधान' हमले को हराने में मददगार साबित होंगी.

प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' हमले को हराने के लिए साम्राज्यवाद–विरोधी, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद–विरोधी और सामंतवाद–विरोधी वर्ग संघर्ष को तेज करें!

इस वर्ग संघर्ष के जरिए जनाधार को बढ़ाते हुए, पार्टी और पीएलजीए को मजबूत करते हुए गुरिल्ला युद्ध को व्यापक और तेज करें!

हमें जनता को वर्ग संघर्ष में व्यापक और जुझारू रूप से गोलबंद करना चाहिए. जनाधार को बढ़ाते हुए, पार्टी और पीएलजीए को मजबूत करते हुए, गुरिल्ला युद्ध को व्यापक और तीव्र करने के द्वारा हमें 'समाधान' हमले को हराना होगा. इसके लिए आगामी समय में निम्नलिखित राजनीतिक, सैनिक और सांगठनिक कर्तव्यों को हासिल करने के लिए अथक कार्य करना होगा :

देशभर में हमारे आंदोलन के सभी इलाकों (शहरी, ग्रामीण और जंगल इलाकों) में, जहां पार्टी मौजूद है, सामाजिक जांच–पड़ताल कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न इलाकों में श्रम के शोषण के रूपों और अतिरिक्त मूल्य की लूट के बारे में अध्ययन कर, सभी उत्पीड़ित वर्गों को वर्ग संघर्ष में गोलबंद करना चाहिए. इसके साथ–साथ राजनीतिक रूप से उत्पीड़न, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दमन और अपमान झेल रहे सभी सामाजिक जनसमुदायों (दलितों, आदिवासियों और महिलाओं एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों) और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं को वर्ग संघर्ष में गोलबंद करना चाहिए. विशेषकर, जमीन समस्या को केंद्र में रखकर सामंती–विरोधी संघर्ष के तहत कृषि क्रांतिकारी संघर्ष को व्यापक करना चाहिए. विस्थापन–विरोधी संघर्ष को साम्राज्यवाद–विरोधी, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद–विरोधी संघर्ष के रूप में विकसित करना चाहिए. किसान समस्याओं पर आंदोलनों को तेज करना चाहिए.

विभिन्न इलाकों की उत्पीड़ित जनता की संघर्ष चेतना व तैयारी पर आधारित होकर जनता को कानूनी–गैरकानूनी, खुले–गुप्त संघर्ष और सांगठनिक रूपों में गोलबंद कर संगठित करना चाहिए. ग्राम/स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक जब का तब प्रधान दुश्मन को अलग–थलग कर, दुश्मनों के बीच के अंतरविरोधों को इस्तेमाल करने योग्य संयुक्तमोर्चा की कार्यनीति को लागू करना चाहिए. मित्र शक्तियों के साथ एकताबद्ध होना चाहिए. ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के हमलों के खिलाफ दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों को गोलबंद कर संगठित करना चाहिए.

राज्य के बलबूते देश के सभी इलाकों में शराब माफिया, रियल एस्टेट माफिया, वन माफिया, रेत माफिया, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में माफिया, चिटफण्ड कंपनियां, बीमा कंपनियां, शेयर बाजार के दलाल – इस तरह कई रूपों में लुटेरी शक्तियां जनता को हर रोज शोषण और उत्पीड़न का शिकार बना रहे हैं. देशी–विदेशी कार्पोरेट घरानों द्वारा खुदरा व्यापार को अपनी चपेट में लेने की वजह से छोटे व्यापारी और खुदरा व्यापारी आर्थिक रूप से गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं. बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त युवा बहुत आक्रोशित है जिसे हमें गोलबंद करना चाहिए.

इस तरह हमें साम्राज्यवाद–विरोधी, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद–विरोधी, सामंतवाद–विरोधी वर्ग संघर्षों में व्यापक जनता को गोलबंद करना चाहिए. इसमें आगे आने वाली सक्रिय और जुझारू शक्तियों को हमारे जनसंगठनों और अन्य निर्माणों में संगठित कर जनाधार को मजबूत करना चाहिए. इस जनाधार के आधार पर पार्टी और पीएलजीए को मजबूत करना चाहिए.

सेंट्रल मिलिटरी कमीशन का आह्वान :

अंतरराष्ट्रीय और देशीय तौर पर मौलिक अंतरविरोध तेज होने के कारण क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बढ़ रही हैं. आर्थिक रूप से कमजोर होती अमेरिका द्वारा लागू आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक नीतियां यूरोप सहित दुनिया के सभी देशों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हैं. अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध शुरू होकर तेज हो गये हैं. व्यापार युद्ध के साथ–साथ अमेरिका और चीन के बीच मुद्रा युद्ध भी जारी हैं. ये विश्व अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं. अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण यूरोप की सुरक्षा के लिए नाटो गठबंधन हेतु अमेरिका पहले जैसे पैसे का आवंटन नहीं कर पा रही है और यूरोपीय देशों पर इसके लिए पैसे के आवंटन बढ़ाने पर दबाव बढ़ा रही है. इससे यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता से बाहर आकर स्वतंत्र नीतियां और व्यवस्था बनाने के लिए तैयार हो रही है.

रूस क्रमशः आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए चीन के साथ मिलकर विश्व को पुनर–विभाजित करने के लिए अमेरिका से स्पर्धा ले रही है. विश्व को पुनर–विभाजित करने के लिए अमेरिका से स्पर्धा लेते हुए चीन द्वारा लागू नीतियों के कारण इसी बीच अफ्रीकी और एशियाई देशों में (जिंबाब्वे, मालद्वीप और श्रीलंका) राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है. आगामी दिनों में और कुछ देशों में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इन सबके कारण एशियाई, अफ्रीकी और लातीन अमेरिकी देशों में साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्ष और तेज हो सकते हैं.

नरेंद्र मोदी के चार साल के शासन के बाद जनता का उससे मोहभंग होना लगातार बढ़ रहा है. इसलिए भाजपा और संघ परिवार हिंदू धर्मोन्माद को देशभर में भड़का रहे हैं. धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन बढ़ाकर आगामी लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के मकसद से कई दांव–पेंच लागू किये जा रहे हैं. नरेंद्र मोदी द्वारा लागू सभी जन विरोधी आर्थिक नीतियों की वजह से स्वाभाविक तौर पर देश के मजदूर, किसान, छात्र, युवा, महिला, छोटे व्यापारी, राष्ट्रीय पूंजीपति व अन्यान्य सभी उत्पीड़ित तबकें परेशान हैं. इस वर्ष रूपए के गिरते मूल्य, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम सहित महंगाई ने मध्यम वर्ग समेत, देश की जनता के जीवन को दूभर कर दिया है. पिछले चार सालों में ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद ने दलितों, आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर तीव्र रूप से हमले किए हैं. शहरी माओवादी कहकर इस वर्ष के जून और अगस्त महीनों में जनसंगठनों के कार्यकर्ताओं व बुद्धिजीवियों पर हमलें तेज किए हैं.

देश के उत्पीड़ित वर्ग, उत्पीड़ित सामाजिक जनसमुदाय और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के रोजमर्रा की और मौलिक समस्याओं से निजात पाने के लिए संसदीय राजनीतिक पार्टियों के, संसदीय व्यवस्था के भ्रम से बाहर आकर इस लुटेरी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर नवजनवादी भारत के निर्माण के लिए जनयुद्ध को तेज करने और उस हेतु जनमुक्ति छापामार सेना में हजारों और लाखों की संख्या में भर्ती करने सीएमसी ने आह्वान किया है.

साथ ही उसने कहा कि प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' हमले का मुकाबला करते हुए पिछले एक साल में हमारे वीर पीएलजीए द्वारा हासिल सफलताओं के बारे में जनता में, कैडरों में और पीएलजीए के योद्धाओं में व्यापक रूप से प्रचार किया जाए.

❍

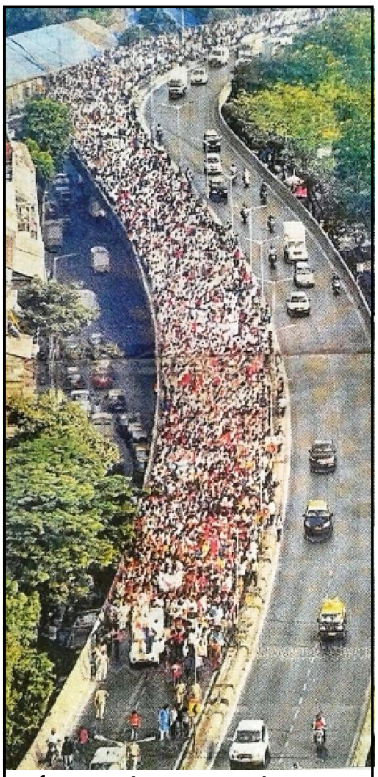

मुंबई की सड़कों पर महाराष्ट्र के करीब 30 हजार किसानों ने 22 नवंबर को मार्च किया. सरकार के सामने कर्जमाफी और सूखा राहत सहित कई मांगे रखीं. आंदोलनकारियों में बड़ी संख्या आदिवासियों की थी.

समाधान को हराने आगे बढ़ती पीएलजीए

(इस वर्ष के सितंबर से दिसंबर तक पीएलजीए द्वारा किए गए हमलों का ब्योरा)

दक्षिण बस्तर डिविजन

25 अक्टूबर को जगरगुंडा एरिया में पीएलजीए द्वारा जब एक माइन का विस्फोट किया गया, पुलिस का एक जवान घायल हुआ.

27 अक्टूबर को तिम्मापुरम – मुरदोंडा के बीच में पीएलजीए द्वारा पुलिस बलों की माईन प्रूफ गाड़ी को उड़ा दिया गया. इस घटना में सीआरपीएफ के चार जवानों को मौके पर ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और दो जवान

घायल भी हुए. जबकि दुश्मन की एक इन्सास एलएमजी को पीएलजीए ने जब्त किया. पुलिस कैंप के नजदीक की गई इस सैनिक कार्यवाही ने जनता व पीएलजीए की ताकत दिखायी. क्रांतिकारी शिविर में जोश व विश्वास बढ़ाया.

5 नवंबर को बीजापुर जिला, बासागुडा के नजदीक पीएलजीए द्वारा लगाए गए माइन को निकालते समय पुलिस का एक जवान घायल हुआ.

12 नवंबर को दक्षिण बस्तर डिविजन, पामेड एरिया, एमपुरम–जारापल्लि गांवों के बीच में पीएलजीए और भाड़े के सरकारी सशस्त्र बलों के बीच में ढाई घंटे तक हुए एक घमासान में पुलिस के दो जवान मारे गए और 5 जवान घायल हो गए. इसमें दुश्मन के दो एके मैग्जीनों को पीएलजीए ने बरामद किया. हालांकि इस घटना में पुलिस को हराने दृढ़संकल्प के साथ लड़ते हुए बटालियन–1 में कंपनी पार्टी कमेटी की सदस्या कामरेड रोशनी ने शहादत को पाया.

18 नवंबर को भेज्जी थाना के अंतर्गत एलाडमडगू गांव के पास पीएलजीए द्वारा किए गए आइइडी विस्फोट में पुलिस का एक जवान मारा गया.

26 नवंबर को किस्टारम इलाके के साकलेर के पास हुई मुठभेड़ में हमारे 9 कामरेड्स शहीद हुए थे. हालांकि इस मुठभेड़ का बहादुराना ढंग से सामना करते हुए पीएलजीए के योद्धाओं ने डीआरजी के दो गुण्डों को मार गिराया और चार से अधिक जवानों को घायल किया. इसके बाद वापस जा रहे पुलिस बलों का पीछा करते हुए पीएलजीए द्वारा किए गए प्रतिरोध में पुलिस के दो जवान घायल हुए.

11 दिसंबर को सुकमा जिले के चिंतागुफा से सीआरपीएफ के जवान एरिया डॉमनेशन के लिए निकले थे. इसी बीच चिंतागुफा के जंगल में पीएलजीए द्वारा किए गए आइईडी विस्फोट में एक जावान गंभीर रूप से घायल हुआ. इससे पुलिस बलों को अपने अभियान को स्थागित करके वापस जाना पड़ा.

पश्चिम बस्तर डिविजन

9 सितंबर को भैरमगढ़ एरिया, बद्देला गांव में सहायक आरक्षक तेल्लम सायबी को पीएलजीए ने मार गिराया. यह तुमला गांव वासी था.

21 सितंबर को बुरगिल गांव के पास पीएलजीए द्वारा लगाए गए बूबीट्रैप विस्फोट होकर पुलिस का एक जवान घायल हुआ.

13 अक्टूबर को चेरपाल बाजार में किए गए पीएलजीए हमले में पुलिस का एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हुआ. लेकिन इस हमले को सफल करने एक मिलिशिया सदस्य ने अपनी जान की कुरबानी दी.

8 नवंबर को दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला–बचेली के आकाशनगर बाजार से खरीददारी कर वापस जाते सीएसएफ

जवानों की मीनी बस को निशाना बनाते हुए पीएलजीए ने बम विस्फोट किया. इसमें सीएसएफ का एक हेडकांस्टेबल सहित 5 जवान मारे गए. दो अन्य जवान घायल हुए.

14 नवंबर को विधान सभा चुनाव की ड्यूटी समाप्त कर वापस जाते बीएसएफ जवानों की गाड़ी को निशाना बनाते हुए बीजापुर जिले के महादेव घाटी – सिंगारबहार नाले के पास पीएलजीए ने एक जबरदस्त विस्फोट किया. इसमें एसअई सहित बीएसएफ के 4, डीआरजी का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुए.

24 नवंबर को बीजापुर के फरसेगढ़ और भोपालपटनम से निकले डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ ने नेशनल पार्क इलाके में गश्त अभियान चलाया. इस दौरान 25 नवंबर को नेलमडगु–कोर्जेर के बीच में पीएलजीए के साथ हुई मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान घायल हुआ.

दरभा डिविजन

28 अक्टूबर को भाजपा नेता व जिला जनपद सदस्य नंदालाल मडावी पर पीएलजीए ने हमला किया. हालांकि इस हमले में नंदालाल बाल–बाल बच गया. वह सिर्फ घायल हुआ था. नंदालाल के ऊपर इसलिए हमला किया गया कि वह उस एरिया में पुलिस द्वारा जारी हिंसा – अत्याचारों, गिरफ्तारियों और हत्याओं का प्रबल समर्थक है. एक आदिवासी होने के बावजूद वह अपनी जड़ों को भूल कर उस इलाके में आदिवासियों को जबरन हिंदू धर्म में शामिल करते हुए न सिर्फ हिंदुत्व कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है बल्कि आदिवासी अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है. ज्ञात रहे, 31 जुलाई 2017 को रक्षा बंधन के दिन राखी बांधने की नौटंकी के बहाने पालनार कन्याश्रम में गए सीआरपीएफ बलों ने वहां की कुछ बालिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था. सरकारी सशस्त्र बलों की अश्लील हरकतों की निंदा करते हुए, उन्हें सजा देने की मांग करते हुए जनता और विभिन्न संगठनों की ओर से जबर्दस्त अवाज उठी. उस समय नंदालाल ने पीड़ित आदिवासी बालिकाओं के पक्ष में नहीं बल्कि दोषियों के पक्ष में खड़ा होकर उन्हें बचाने के लिए कमर कसी थी. इस तरह लुटेरे वर्गों का एजेंट बन कर जनता को क्षति पहुंचा रहा है. इन सारे अपराधों की बदौलत जन अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर अमल करते हुए पीएलजीए को नंदालाल पर हमला करना पड़ा.

30 अक्टूबर को दंतेवाडा जिले के किरंदूल आरनपूर नीलम गांव के पास रोड निर्माण में लगी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए मोटार साइकिलों पर आने वाले पुलिस बलों पर पीएलजीए द्वारा हमला किया गया. इसमें पुलिस का एक अधिकारी और दो जवान मारे गए. दुख की बात यह है कि इस हमले में पुलिस बलों के साथ दौरा करने वाले दूरदर्शन के एक कैमरा मेन की जान भी चली गई. इस तरह की घटनाएं न घटे, इसके लिए पार्टी की तरफ से कईयों बार ग्रामीणों, मीडिया कर्मियों व अन्य कर्मचारियों से अपील की गई कि वे पुलिस व अन्य सरकारी सशस्त्र बलों के साथ सफर न करें. इस विज्ञप्ति को नजरअंदाज करने की वजह से यह जानी नुकसान हुआ. इस घटना में एक एके–47 सहित अन्य सैनिक सामाग्री पीएलजीए के हाथों में आ गईं. चूंकि घटना स्थल पर यह नहीं पता चला कि मृतक पुलिस कर्मी नहीं बल्कि एक मीडिया कर्मी थे, उनका कैमरा भी पीएलजीए बलों ने जब्त किया था. हालांकि सच्चाई का पता चलने के बाद उस कैमरा को वापस देने का फैसला संबंधित पार्टी कमेटी द्वारा लिया गया.

30 नवंबर को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में गश्त पर निकले पुलिस बलों पर पीएलजीए ने फायरिंग करके आइईडी ब्लास्ट किया. इसमें सीआरपीएफ का एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया.

उत्तर बस्तर डिविजन

2 नवंबर को रावघाट एरिया के मरकानार गांव के पास पीएलजीए द्वारा किए गए कुकर बम हमले में पुलिस के दो जवान घायल हुए.

11 नवंबर को कोयलीबेडा क्षेत्र के गट्टाकल गांव के पास पीएलजीए द्वारा किए गए आइईडी विस्फोट में बीएसएफ का एक सब इन्स्पेक्टर महेंद्र सिंह मारा गया और दो जवान घायल हुए.

माड डिविजन

रोड और पुलिया निर्माण की सुरक्षा के लिए लगभग 50 की तादाद में आए पुलिस बलों के ऊपर 15 दिसंबर को इंद्रावती एरिया के बोदली और फुंडरी के बीच में पीएलजीए द्वारा किए गए कुकर विस्फोट में पुलिस का एक एसआई और दो आरक्षक घायल हुए. इनमें से एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हुआ.

आरकेबी डिविजन

18 अक्टूबर को राजनांदगांव जिले के मोहला इलाके में चुनाव के पहले गश्त करते आइटीबीपी के जवानों को निशाना बनाते हुए पीएलजीए ने राजाडेरा के नजदीक कुकर बम विस्फोट किया. इस विस्फोट में तीन जवान घायल हुए.

गढ़चिरौली डिविजन

29 नवंबर को छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली के एटापल्ली तहसिल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गट्टेपल्ली–रेगड़ी के बीच सड़क निर्माण कार्य में लगे 16 वाहनों को पीएलजीए ने आग के हवाले कर दिया. इनमें 10 जेसीबी, तीन ट्रेक्टर्स, दो मोटरसाइकिल व एक पिकअप शामिल है. इससे लुटेरे वर्गों को लगभग तीन करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. ❍

जनयुद्ध में मिलिशिया की बढ़ती भागीदारी

(सरकारी सशस्त्र बलों के खिलाफ दंडकारण्य में जारी सशस्त्र प्रतिरोध में पीएलजीए की बेस फोर्स यानी मिलिशिया की अहम हिस्सेदारी है. मिलिशिया अक्सर पीएलजीए के प्रथम व द्वितीय बलों के साथ मिल कर प्रतिरोध में भाग लेती है, अलग से भी प्रतिरोध करती है. हमें उपलब्ध रिपोर्टों में से इस वर्ष के जून से लेकर नवंबर तक सिर्फ मिलिशिया द्वारा अंजाम दी गई कार्यवाहियों के बारे में इधर छाप रहे हैं.

दंडकारण्य में जारी सशस्त्र प्रतिरोध में स्पाइक होल्स (नुकीले छड़ों से युक्त गड्ढ़ों) वर्तमान में पुलिस बलों के बीच कदम-कदम पर दहशत पैदा कर रहे हैं. सिर्फ चुनाव के वक्त ही स्पाइक होल्स में गिर कर दक्षिण बस्तर में पुलिस के 52 जवान और दरभा डिविजन में पुलिस के 15 जवान घायल हुए. स्पाइक होल्स को बनाने में भी न सिर्फ मिलिशिया बल्कि क्रांतिकारी जनता की अहम भूमिका रहती है. जनता के साथ मिलकर मिलिशिया न सिर्फ इन्हें बनाती है बल्कि इनके बनाने में जनता का नेतृत्व करती है. स्पाइक होल्स बनाने में मिलिशिया की भूमिका की वजह से स्पाइक होल्स में गिर कर पुलिस के घायल होने की खबरों को भी यहीं पर शामिल किया जा रहा है.

-संपादक मंडल)

दक्षिण बस्तर डिविजन

10 जून को मिनपा के नजदीक मिलिशिया द्वारा लगाए गए बूबीट्राप की चपेट में आने से डीआरजी के दो गुंडे घायल हो गए.

23 जून को बासागुडा, सारकिनगुडा, बोट्टेम कैंपों से निकले पुलिस बलों ने पश्चिम बस्तर के पिडिया और तुमनार गांवों पर हमला किया. 25 को जब पुलिस बल वापस जा रहे थे, गोटोड मंडेल और तर्रेम के बीच में मिलिशिया द्वारा तीन जगहों पर विस्फोट किए गए बूबीट्राप्स की चपेट में आकर पुलिस के एक जवान की मौत हुई. जबकि सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हुए.

शहीद सप्ताह को विफल करने के लिए एक हफ्ते पहले ही बासागुडा के आस पास के गांवों में बड़ी संख्या में आए पुलिस बलों ने अभियान चलाया. उस समय 25 जुलाई को चिना तर्रेम गांव के पास मिलिशिया द्वारा लगाया गया पाईप बम विस्फोट होकर कोबरा बटालियन के दो जवान घायल हुए. इसी अभियान के दौरान स्पाइक होल्स में गिर कर 8 जवान घायल हुए. इस प्रतिरोध से हैरान पुलिस बलों ने अपने अभियान को रोक दिया, जिससे शहीद सप्ताह को मनाने में जनता को कोई बाधा नहीं आई.

3 अगस्त को बासागुडा हाट बाजार में सीआरपीएफ जवानों पर मिलिशिया द्वारा किए गए हमले में तीन जवान घायल हुए, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हुए.

7 अगस्त को जगरगुंडा से सुरपन और नीलमपारा गांवों में गश्त करके पुलिस बल जब वापस जा रहे थे, कोत्तगुडा के पास मिलिशिया द्वारा लगाए गए बूबीट्राप की चपेट में आकर सीआरपीएफ का एक कमांडेंट गंभीर रूप से घायल हो गया.

25 अक्टूबर को मल्लेवागु के नजदीक मिलिशिया द्वारा किए गए माइन विस्फोट में पुलिस के तीन जवान घायल हुए.

27 अक्टूबर को मल्लेपाड के नजदीक स्पाइक होल्स में गिर कर पुलिस के चार जवान घायल हो गए.

पश्चिम बस्तर डिविजन

22 अगस्त को रेड्डी गांव के पास सरकारी सशस्त्र बलों को आपूर्तियां ले जा रही गाड़ी पर मिलिशिया ने हमला किया. इस हमले में मिलिटरी व सिविल कपड़ों और स्टेशनरी को मिलिशिया ने जब्त किया.

12 सितंबर को बीजापूर से गंगालूर के रेड्डी गांव के लिए जा रही सरकारी सशस्त्र बलों की खाद्य सामग्री को मिलिशिया ने जब्त किया.

गंगालूर एरिया के पेद्दाजोजुर, चिनाजोजुर गांवों पर न सिर्फ हमले करने बल्कि जतीनदास शहादत दिवस जिसे राजनीतिक बंदियों के अधिकार दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है, के आयोजनों में बाधा डालने के लिए 12–14 सितंबर को पुलिस बल निकले थे. उनमें से दो लोग स्पाइक होल में गिर कर घायल हो गए.

पार्टी के स्थापना सप्ताह को क्रांतिकारी जनता न मना सकें, इसके लिए 19 से 21 सितंबर तक बीजापुर जिले के गंगालूर एरिया में डीआरजी, जिला बल, सीआरपीएफ ने एक अभियान चलाया. इस दौरान हीरील, कुर्वीस, पूंबाड, बुरगिल आदि गांवों में गश्त करके जब पुलिस बल वापस जा रहे थे, मिलिशिया द्वारा लगाया गया बूबीट्राप विस्फोट होकर पुलिस का एक जवान घायल हुआ. इसी दौरान स्पाइक होल ने पुलिस के दो जवानों को अपनी चपेट में ले लिया, तो वो गंभीर रूप से घायल हो गए.

गंगालूर इलाके के एडसूम, पेदाम, पिडिया और इरमागुंडा गांवों पर हमलें करके जब पुलिस बल जा रहे थे स्पाइक होल्स में गिर कर दो जवान घायल हो गए. यह घटना 25 सितंबर को घटी थी.

25–26 सितंबर को कोरमा, मुरुंगा गांवों पर हमले कर जब पुलिस बल वापस जा रहे थे, स्पाइक होल्स में गिर कर दो जवान घायल हो गए. बाद में घायल जवानों को ले जाने के लिए जब डीआरजी गुंडे मोटर साईकलों पर सवार होकर आ रहे थे, पदेडा गांव के पास मिलिशिया द्वारा लगाया गया बूबीट्राप विस्फोट होकर एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हुआ.

चुनाव के समय में भैरमगढ़ एरिया में पुलिस के पांच

मुठभेड़ों के नाम पर निर्मम हत्याएं

ज्ञात है कि समाधान के नाम पर जनता व क्रांतिकारी आंदोलन पर भीषण दमन का प्रयोग किया जा रहा है. जिसमें मुठभेड़ों के नाम पर हत्याएं आम बात हो गईं. ऐसी कुछ निर्मम हत्याओं की खबरें हमें बहुत ही विलंब से मिलीं. हालांकि इन खबरों की गंभीरता को नजर में रखते हुए हम उन्हें छाप रहे हैं. ऐसे में इस वर्ष के फरवरी से दिसंबर तक की घटनाएं इस रपट में शामिल हैं.

– संपादक मंडल

दक्षिण बस्तर डिविजन

17 फरवरी, 2018 को जगरगुंडा एरिया, नागारम एलओएस पर पुलिस ने हमला किया. हालांकि इस हमले से गुरिल्ला सदस्या कामरेड सन्नी सुरक्षित बच निकल कर नेलागाडूम गांव में पनाह ली हुई थी. वहां साधारण कपड़े पहन कर वह जनता के बीच में छिप गई थीं. पुलिस बैच में मौजूद पीएलजीए के भगोड़े गद्दारों ने कामरेड सन्नी को पहचाना, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. इसी तरह गांव की मिलिशिया में कार्यरत 27 वर्षीय माडवी नंदाल समेत और एक युवक को भी पुलिस ने पकड़ा था. दरअसल उस दिन गांव में गादे नामक एक पारंपरिक त्यौहार मनाया जा रहा था, कामरेड नंदाल उस त्यौहार में भाग लेने घर गए थे. पुलिस बलों ने कामरेड्स सन्नी और नंदाल दोनों को बुरी यातनाएं देकर उनकी हत्या करके त्यौहार के हंसी–खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया.

18 फरवरी, 2018 को एलाडमडुगु गांव के नजदीक कोंटा एरिया की क्रांतिकारी जनताना सरकार कमेटी सदस्य कामरेड भीमाल को पुलिस ने पकड़ा था. 45 वर्षीय कामरेड भीमाल कोंटा क्षेत्र के मराईगुडा निवासी थे. वह साधारण जिंदगी बिताते हुए अंशकालीन रूप से क्रांतिकारी आंदोलन में कार्यरत थे. पुलिस ने उन्हें पकड़ कर बुरी यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की.

3 मई, 2018 को किष्टारम एरिया, वेरूम गांव पर हमला करके मिलिशिया के दो सदस्य – 26 वर्षीय मडकाम कोनाल और जोगाल को पुलिस ने उनके घरों से पकड़ लिया. बाद में जाटम और निमलगुडेम के बीच में गोली मार कर दोनों की हत्या की गई. पुलिस ने अपने कुसूर को छिपाने के लिए इस मनगढ़ंत कहानी को प्रचार किया कि मुठभेड़ में बटालियन के दो सदस्यों को मार गिराया.

14 जून, 2018 को गट्टापाड में एक शादी समारोह में नाचने वाले समूह के ऊपर पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें उसी गांव के माडवी जोगा और सेमेल गांव के पोडियम भीमा की मौत हुई. माडवी जोगा ने विगत में पेशेवार क्रांतिकारी के तौर पर गुरिल्ला दस्ते में काम किया था. बाद में वह पार्टी छोड़ कर घर गए थे. इस समाचार को पाकर पुलिस ने जोगा को पकड़ने के लिए उनके भाई की शादी के दिन को चुना. अपने भाई के शादी में नाचते जोगा के ऊपर पुलिस द्वारा गोलियां बरसायी गईं. घायल अवस्था में जोगा को पकड़ कर बेरहमी से यातनाएं देकर उनकी हत्या की गई. जबकि पोडियम भीमा डीएकेएमएस सदस्य थे. इस तरह दो लोगों को मारकर पुलिस ने शादी समारोह को मातम में बदल डाला. लेकिन पुलिस का खूनी प्यास इससे भी बुझा नहीं. दोनों की लाशें लेकर वापस जा रहे पुलिस बलों ने तोकेल व इत्तागुफा के बीच के जंगल में निहत्थे जा रही मिलिशिया कामरेडों को देखा था. उनके नजदीक आने के बाद पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें मिलिशिया कमांडर कामरेड देवाल घायल हुए. घायल अवस्था में उन्हें पकड़ कर चिंतागुफा के कब्रिस्तान में ले जाकर निर्मम यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की गई. 25 वर्षीय कामरेड देवाल टेकालपारा गांव वासी थे.

30 जून, 2018 को केरलापाल एरिया के बड़ेसट्टी पंचायत के सिंगानपारा निवासी कामरेड जग्गू को पुलिस बलों ने उनके घर में पकड़ लिया. पुलिस ने बर्बर तरीके से कामरेड जग्गू के हाथ व पैर काट कर बुरी यातनाएं देकर उनकी हत्या की. 33 वर्षीय कामरेड जग्गू डीएकेएमएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे.

1 जुलाई, 2018 को विशेष सैनिक ऑपरेशन के नाम

जवान स्पाईक होल्स में गिरकर घायल हुए जिनमें से एक जवान की मौत हुई.

नेशनलपार्क एरिया के सागमेट्टा, मूकावेल्ली, अलवाडा, पेद्दागुंडापूर, मोकरम गांवों के दायरे में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुलिस बलों ने गश्त चलायी. इस दौरान सागमेट्टा व मूकावेल्ली गांवों के ऊपर हमलें किए गए. अपना आतंक खतम करके वापस जाते समय स्पाइक होल में गिर कर एक जवान घायल हुआ.

7–9 नवंबर को किए गए गश्त अभियान में भी भैरमगढ़ एरिया में पुलिस के दो जवान गंगालूर एरिया में एक जवान स्पाइक होल्स में गिर कर घायल हो गए.

दरभा डिविजन

9 नवंबर को दंतेवाड़ा जिले के मलिगेंर एरिया के अरनपुर इलाके में एरिया डॉमनेशन के लिए निकले सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी के जवानों में से कोण्डासवली के बीच स्पाईक होल्स में गिरकर सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया. ❍

पर हजारों पुलिस बलों ने कुम्मोम, मड़कागुडेम, दाडल, जिलोर, इत्तागुडेम, मीनागट्टा, बोत्तलंका, मेट्टागुडेम, मडपे दुलोड, कयेर दुलोड गांवों पर हमलें किए. पुलिस के हत्थे न चढ़ जाएं, इसलिए गांवों की सभी जनता ने भाग कर जंगल में पनाह ली. छोटे बच्चों सहित सभी लोग दिन व रात जंगल में भूखे–प्यासे रह गए. अगले दिन यह पता करते हुए कि पुलिस बल वापस गए या नहीं, लोग अपने–अपने गांवों की तरफ जा रहे थे. उसी वक्त मडकागुडेम में लोगों के एक जमावड़े पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई. इसमें मौके पर ही कुम्मोम गांव के रव्वा भीमाल की मौत हुई. जबकि मडकागुडेम गांव के डीएकेएमएस अध्यक्ष बाड़से माडकाल ने घायल होकर वहां से कुछ दूर तक भाग कर अपनी जान छोड़ दी.

10 जुलाई, 2018 को मछली पकड़ने गए कामरेड मुत्तन्ना को पुलिस ने धरदबोच लिया. लगभग तीस वर्षीय कामरेड मुत्तन्ना मडपे दुलोड गांव वासी थे. और उस वक्त वे पंचायत मिलिशिया कमांडर का दायित्व निभा रहे थे. जब मुत्तन्ना पुलिस के हाथों में थे, तभी काम पर जा रहे बटालियन के सदस्य कामरेड उयके माडाल को भी पुलिस ने पकड़ लिया. दोनों को मिनपा जंगल ले जाकर बुरी तरह यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की गई.

13 जुलाई को किष्टारम एरिया के सोमला गूडेम गांव में जब क्रांतिकारियों की एक छोटी व निहत्थी टीम ग्रमीणों की बैठक कर रही थी, अचानक पुलिस ने हमला किया. हालांकि टीम के अन्य कामरेड्स सुरक्षित निकलने में सफल हो गए लेकिन टीम की एक सदस्या, केएएमएस ऑर्गनाइजर कामरेड हिडमे पुलिस की गिरफ्त में आ गई. पुलिस गुंडों ने उनके साथ बेरहमी से सामूहिक अत्याचार करके बुरी तरह यातनाएं देकर उनकी हत्या की.

3 अगस्त को जगरगुंडा एरिया के बासागूडा हाट बाजार में पुलिस बलों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में उयका गुंडाल की मौत हुई.

3 अक्टूबर को केरलापाल एरिया के मूलेर गांव के तीन मिलिशिया सदस्य – कामरेड माडवी हिडमा, कडती मल्ला और कडती हिरिया – जब पुलिस के हाथ लग गए थे, पुलिस ने क्रूरतापूर्वक यातनाएं देकर उनकी हत्या की.

19 नवंबर को पुलिस द्वारा कामरेड सिंगाल की हत्या की गई. पेशेवर कार्यकर्ता कामरेड सिंगाल अपने परिवार को मिलने के लिए अपने गृहगांव केरलापाल एरिया के सिंगम गांव में गये थे. जब वह निहत्थे अपने खेत में काम कर रहे थे इसकी सूचना पाने वाले पुलिस बलों ने हमला करके कामरेड सिंगाल को धरदबोचा. बाद में क्रूर यातनाएं देकर उनकी हत्या की.

कामरेड शांति की निर्मम हत्या को पुलिस ने मीडिया में बेशर्मी से इस तरह दिखाया

पश्चिम बस्तर डिविजन

2 जून को भैरमगढ़ एरिया के एंड्री गांव के डीएकेएमएस सदस्य माडवी सुनील जब खेतों की तरफ जा रहे थे, पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनकी हत्या की.

16 अगस्त को भैरमगढ़ एरिया के कमालूर एलओएस दायरे के भांसी गांव मासापारा में जब गुरिल्ला कामरेडों द्वारा आमसभा का आयोजन किया जा रहा था, अचानक पुलिस ने हमला किया. हालांकि इस हमले से जनता व पीएलजीए के अन्य कामरेड्स सुरक्षित रूप से बच निकलने में कामयाब हुए थे लेकिन एरिया कमेटी सदस्या, सीएनएम डिविजन कमेटी की सदस्या एवं सीएनएम की एरिया अध्यक्षा कामरेड कारम रुकनी पुलिस के हाथ लग गयी थी. क्रूर पुलिस बलों ने कामरेड रुकनी के साथ बेरहमी से यौन अत्याचार करके उनकी हत्या की.

19 अक्टूबर को भैरमगढ़ एरिया के मिरतुल पुलिस स्टेशन के दायरे में हाट बाजार जा रहे 50 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था. बाद में उनमें से तीन लोगों – ओयम सुकलू (वेच्चा गांव), पोडियम जग्गु (पमरा गांव, मिलिशिया कंपनी का सेक्शन कमांडर), और तेल्लम पोदियाल (मद्दुम गांव, जीआरडी कमांडर) को बेरहमी से यातनाएं देकर अगले दिन मद्दुम गांव के नजदीक गोली मार कर उनकी हत्या की.

11 नवंबर को मरकोड गांव पर पुलिस ने हमला किया. पुलिस बलों को देख कर भागने वाले एक साधारण ग्रामीण पर पुलिस बलों ने बर्बर तरीके से कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या की.

25 नवंबर को नेशनलपार्क इलाके के नेलमडुगु गांव में पीलूर पंचायत के जनताना सरकार अध्यक्ष कामरेड सोडी कुम्मा को पुलिस बलों ने पकड़ कर यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की.

इसी दिन पुलिस ने गंगालूर एरिया के बुर्गिल गांव के ओयम वेल्लाल को पकड़ कर, बाद में गोली मार कर उनकी हत्या की.

दरभा डिविजन

12 अक्टूबर को कांगेरघाटी एरिया, चांदमेट्टा गांव पर पुलिस ने हमला किया. पुलिस को देख कर भागने वाली जनता पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी में जन संगठन के सदस्य कामरेड अडमाल की जान चली गई.

1 दिसंबर को गुड्रापाल गांव में निहत्थी रही पार्टी सदस्या कामरेड शांति को पुलिस ने पकड़ कर बाद में उसकी हत्या की. ❍

शहीदों की बलिदानी राह पर आगे बढ़ेंगे!

का. प्रमीला

का. भीमा

का. राजे

का. गागरु

का. सोमडी (गार्ड)

का. गंगा

का. शांति

का. पोज्जा

का. हिडमे

इस अंक की कालावधि अक्टूबर–दिसंबर 2018 के बीच में दंडकारण्य के जनयुद्ध–जनसंघर्ष को आगे ले जाने के क्रम में कई वीर योद्धाओं ने अपनी जान की कुरबानी दी. हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 नवंबर, 2018 को दक्षिण बस्तर डिविजन, साकलेर गांव के पास दुशमन द्वारा किए गए एक बड़े हमले का मुकाबला करते हुए 9 कामरेडों ने शहादत को पाया. शहीदों में जोन इंस्ट्रक्टर टीम इंचार्ज कामरेड तातीं भीमा (सूर्या) – डीवीसीएम, दक्षिण बस्तर डिविजन के सीएनएम की अध्यक्षा पोडियम राजे–एसीएम, गार्ड जिम्मेदारी में कार्यरत माडवी सोमडी–पीएम, सीएनएम में कार्यरत मडकम सोमडी–पीएम, मडकम गंगाल (अर्जुन)–पीएम, माडवी शांति–पीएम, मिलिशिया कामरेड्स मडकम पोज्जा (सल्लातोंग गांव), सोडी हिडमे (कन्नेमरका गांव), जन संगठन नेता मडकम जोगा (गुंड्राई गांव) शामिल थे. हृदयाघात के चलते 16 दिसंबर, 2018 की शाम 7.30 बजे को पूर्व बस्तर डिविजन के आमदायी एरिया में कार्यरत कामरेड गागरु सलाम (55) का निधन हुआ था. 12 अक्टूबर, 2018 को एओबी जोन में पुलिस ने मलकनगिरी डिविजनल कमेटी की सचिवालय सदस्या कामरेड प्रमीला (शारदा, जिलानी, मीना) की हत्या की.

परिशिष्ट

प्रभात

दंडकारण्य कि मुक्ति के लिए अपनी जान की कुरबानी देने वाले

साकलेर अमर वीर शहीदों को लाल–लाल सलाम

का. भीमा का. राजे शह. सोमडी शह. गंगा शह. शांति

का. पोज्जा का. हिडमे

कामरेड तातीं भीमा (सूर्या)

प्रभात इन सभी कामरेडों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके द्वारा अपनाए गए आदर्शों से सीखते हुए, उनकी कुरबानी के रास्ते पर आगे बढ़ने अपने पाठकों से आग्रह करता है.

उपरोक्त कामरेडों की जीवनियों के अलावा उन सभी कामरेडों की जीवनियों को जो हमें विलंब से प्राप्त हुईं हैं और प्रभात के पिछले अंकों में छपी नहीं हैं, इस अंक के परिशिष्ट में छाप रहे हैं.

– संपादक मंडल

''हमें नहीं चाहिए, हमारे पेट पर मारने वाली सड़कें!''

यह नारा नीलावाया और उसके आस–पास की जनता के गलों से तब उठ पड़ा, जब सड़क के चौड़ीकरण के लिए उनकी फसल बरबाद की गई. उनकी जमीन छीनी गई. उनकी आजीविका के लिए अहमियत रखने वाले कई पेड़ व पौधे काटे गए.

विकास के नाम पर सरकार द्वारा किया जा रहा हर काम जनता के लिए विनाश ही साबित होता है. शासक वर्गों का कहना है कि रोड, रेल लाइन, बांध, खदान, कंपनी–कारखाना, पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के कैंप... ये सब विकास का हिस्सा हैं. लेकिन ये सब जनता के जल, जंगल, जमीन को हड़प कर ही बनाए जाते हैं, और हड़पने के लिए ही बनते हैं. इसीलिए इस विकास नमूने के खिलाफ देश भर में जनांदोलन सामने आ रहे हैं. इसी तरह दरभा डिविजन (दंतेवाडा जिला) के मलिंगेर एरिया में भी एक जबर्दस्त जनांदोलन सामने आया.

सड़क के चौड़ीकरण के विरोध में रैली निकाल कर आक्रोश जताती जनता

दंतेवाडा–जगरगुंडा रोड से कीकिरीगुडा चौक से होते हुए अंदरूनी इलाके के नीलवाया और बुर्गुम गांवों तक 5–6 अक्टूबर को रोड निर्माण का काम शुरू किया गया. इसके लिए सीआरपीएफ की सुरक्षा में आई लेवेलिंग गाड़ियां, जेसीबी, टिप्पर आदि के सहारे मजदूरों के बिना ही तेज गति से काम होने लगा. इसके चलते जनता की कोसरा (एक प्रकार के छोटा अनाज जो धान के बदले में उगाया जाता है) फसल बर्बाद हुई. महुआ, आम, छिंद, ताड़, कोसुम, इमली, जंबू के कई वृक्ष जो आदिवासी जनता की आजीविका के लिए अहम हैं, काटे गए. पानी की सुविधा के लिए जनता द्वारा बनाए गए बांधों को तहस–नहस किया गया.

इस विनाश व बर्बादी को देख कर जनता बेहद खिन्न हो गयी. हालांकि जनता का दुख आक्रोश में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा. और उस आक्रोश ने आंदोलन का रूप ले लिया. 9 से 11 अक्टूबर यानी पूरे तीन दिन जनता ने जुझारू संघर्ष किया. पंचायत विकास समिति के बैनर तले बुरगुम, नीलावाया और पोटाली पंचायतों की महिलाओं, बूढ़ों व बच्चों सहित लगभग 300 लोगों, जिनके हाथों में 'सड़कों के चौड़ीकरण का विरोध करेंगे', 'सड़क निर्माण के लिए हमारी उपजाऊ जमीन, हमारे जीवनोपयोगी महुआ, छिंद, इमली पेड़ों को ध्वस्त करने का विरोध करेंगे', 'पुलिस कैंपों का विरोध करेंगे' आदि नारें अंकित तख्तियां थी, ने रैली की. एक किलोमीटर के दायरे को कव्हर करने वाली इस रैली में 'पेसा कानून का उल्लंघन रोक दो', 'रोड चौड़ीकरण बंद करो', 'बोयी हुई जमीन को खोदना बंद करो', 'विकास के नाम पर विनाश मत करो' आदि नारें गूंज उठे. संघर्षरत जनता ने इस तरह रैली के शक्ल में जाकर रोड निर्माण कार्यों को रोका. निर्माण कार्यों में लगी गाड़ियों के आगे खड़े सरकारी सशस्त्र बलों ने अपनी बंदूकों को तान कर जनता को पीछे धकेलने की कोशिश की, तो जनता ने पुलिस बलों को. काटे गए पेड़ों की डालियों और अपने खेत औजारों को ही अपने हथियार बना कर जनता पुलिस के साथ भिड़ गयी. इस झूमाझटकी में एक महिला की चूड़ियां टूट गईं. टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों के साथ उस महिला ने पुलिस जवानों के चेहरे को खरोंचा. पुलिस बलों के बैग छीनते हुए उनके कपड़े खींचते हुए जनता ने पुलिस बलों को हैरान कर दिया. जनता ने ये नारे जम कर लगाएं कि 'हमारे पास कोई बस, गाड़ी या मोटार साइकिल नहीं है. इसलिए हमें नयी सड़क की कोई जरूरत नहीं हैं.' 'हमें नहीं चाहिए, हमारे पेट पर मारने वाली सड़कें'. जनता ने पुलिस बलों से यह सवाल पूछा कि वहां पुलिस बल क्यों आए? रोड निर्माण के लिए, तो ठेकेदार को आना चाहिए था. पुलिस के यह कहने पर कि जनता को किसी ने सिखा कर भेजा है, (सरकार व सरकारी बलों को हर किसी आंदोलन के पीछे माओवादी ही दिखाई देते हैं.) जनता ने अपनी दलील दी कि उन्हें किसी ने नहीं भेजा. उनकी जमीनें, उनकी फसलें और उनकी समस्याएं उन्हें वहां ले आईं.

पुलिस बलों ने जब एक व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, तो संघर्षरत लोगों ने यह कहते हुए कि एक को नहीं, पकड़ना है, तो सभी को पकड़ कर जेल में डाल दें, उसे बचा लिया.

तीन दिन तक चले जनता के इस जुझारू संघर्ष के सामने तात्कालिक ही सही पुलिस बलों को झुकना ही पड़ा. आखिर वे काम बंद करके चले गए. इस संघर्ष ने जनता के साहस व विश्वास को बढ़ाया. संघर्षरत जनता

जोर–शोर से मनाए गए क्रांतिकारी दिवस

जेल बंदियों का अधिकार दिवस

उत्तर बस्तर डिविजन

रावघाट एरिया

रावघाट एरिया में 13 सितंबर–जतीन दास के शहादत दिवस को जेल बंदियों के अधिकर दिवस के रूप में मनाया गया. इस मौके पर केंद्रीय कमेटी के आह्वान के मुताबिक जेल बंदियों के समर्थन में एवं सरकारी दमन के खिलाफ एरिया में बैनर बांधे गए. पोस्टर चस्पा किए गए. पर्चे बांटे गए. इसके अलावा जेल बंदियों के परिवारों की बैठक करके उन्हें ढांढस बांधी गई. उनकी जरूरतों की आपूर्ति के लिए हर संभव मदद की गई. जेल–कोर्ट के लिए आर्थिक सहायता भी की गई.

प्रतापुर एरिया

फिलहाल एरिया के 52 लोग माओवादी मामलों में जगदलपुर, रायपुर और दुर्ग जेलों में बंद हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है. इनमें से एक को आजीवन कारावास और एक को दस वर्ष की सजा सुनाई गई. और पांच लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई थी. लेकिन जनता के संघर्ष के चलते उनकी सजाएं रद्द हो गईं. माओवादी मामलों के अलावा अन्य मामलों में भी 15 लोग जेल में सड़ रहे हैं. जेलों की बदहाल परिस्थितियों के कारण जेलों से छूट कर आने वाले कई लोग टीबी, केंसर, घुटने दर्द, आंख की समस्याएं, पीलिया आदि बीमारियों से जूझ रहे हैं. जेल बंदियों के परिवार भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं. जेल बंदियों को छुड़ाने के लिए कुछ परिवारों ने लाखों रुपये खर्च किए हैं जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई. सूखे और बीमारियों की वजह से उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई. इस स्थिति को कुछ हद तक संभालने के लिए क्रांतिकारी जनताना सरकारों द्वारा गांवों से चावल और पैसे इकट्ठे किए गए. इकट्ठे किए गए 34 क्विंटल चावल और रु.38,600 की रकम को 13 सितंबर के मौके पर बांट दिया गया.

किसकोडो एरिया

जेल बंदियों के अधिकार दिवस के मौके पर एरिया के जिन सात लोग जेलों में बंद हैं उन लोगों की मदद के लिए पांच हजार रुपयों का आर्थिक सहयोग किया गया. जेल से रिहा होकर आऐ लोगों को मिल कर उनके साथ बातचीत की गई.

पार्टी स्थापना दिवस की वर्षगांठ

पूर्व बस्तर

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के 14 वें स्थापना दिवस के मौके पर कुछ गांवों में आमसभाएं आयोजित की गईं. पोस्टरों एवं बैनरों के जरिये जनता में पार्टी का संदेश पहुंचाया गया. आमदाई इलाके में आयोजित जनसभा में 823 जनता शामिल हुई जिसमें महिलाओं की तादाद 257 थी. गांव–गांव में जनता की एकता को बनाए रखते हुए जनताना सरकारों को मजबूत एवं उनका विस्तार करने का आह्वान किया गया. दमन अभियानों को हराने के लिए जन संघर्षों को तेज करने की आवश्यकता पर वक्ताओं ने अपने भाषणों में जोर दिया. चेतना नाट्य मंच के कामरेडों की कला प्रस्तुति ने क्रांतिकारी जोश को और बढ़ाया.

माड डिविजन

इंद्रावती

एरिया में पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर जन संगठनों और क्रांतिकारी जनताना सरकारों के कमेटी सदस्यों को सीसी संदेश क्लस के रूप में बताया गया.

ने यह ठान ली कि जान देंगे पर जमीन नहीं. इस संघर्ष ने और एक बार इस ऐतिहासिक सच्चाई को साबित कर दिया कि अगर बड़े पैमाने पर जनता निडरता से आगे बढ़ती है, तो सशस्त्र पुलिस बलों को भी पीछे मुड़ना ही पड़ता है.

हालांकि कुछ दिनों तक रोड चौड़ीकरण काम रोक दिया गया हो, लेकिन यह काम फिर से शुरू किया गया था. जनता के दुख, आक्रोश, आंदोलन को नजरअंदाज करके कॉर्पोरेट घरानों के फायदे के लिए उनकी लूट को और सुगम करने के लिए जनता की जिंदगियों की बलि चढ़ाते हुए रोड चौड़ीकरण को आगे बढ़ा रहे शासक वर्गों और उनके भाड़े के सशस्त्र बलों को सबक सिखाने के लिए एवं जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए अब जनता की सेना को आगे बढ़ना पड़ा. रोड निर्माण में लगी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए मोटार साइकिलों पर आने वाले सीआरपीएफ बलों पर रोड निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों को ही अपने कव्हर बना कर महज 5 गजों की दूरी से हिम्मत व आत्मबलिदान की भावना के साथ पीएलजीए द्वारा किए गए हमले में एक अधिकारी सहित सीआरपीएफ के तीन जवान मारे गए. एक एके–47 सहित कुछ सैनिक सामाग्री को भी इस हमले में पीएलजीए ने जब्त किया.

पर्चों, पोस्टरों, बैनरों के साथ पूरे एरिया में व्यापक रूप से प्रचार किया गया. 100 से अधिक सीएनएम सदस्यों ने कई टीमें बन कर इस प्रचार की अगुआई की. प्रचार के बाद इंद्रावती एलओएस क्षेत्र में एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें 10 आरपीसी के गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया. भाग लेने वाले लोगों में 382 महिलाएं, 610 पुरुष, 192 बच्चियां और 146 बच्चे थे. इनके अलावा सैकड़ों मिलिशिया सदस्यों ने भी न सिर्फ इसकी सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई बल्कि वे इस सभा का हिस्सा बन गये थे.

कुतुल एरिया

तीन जन संगठनों, जनताना सरकार और स्थानीय एलओएस के सदस्यों ने पोस्टर, बैनर के साथ एरिया में पार्टी स्थापना दिवस के बारे में प्रचार किया. बाद में 2–3 आरपीसीयों की जनता की भागीदारी से अलग–अलग जगहों में पांच सभाओं का आयोजन हुआ. इन सभाओं में कुल मिलाकर 960 महिलाएं, पुरुष 1200 और 190 बच्चे शामिल हुए थे. 50 सीएनएम कलाकारों ने अपने सांस्कृतिक प्रदर्शनों के जरिए इन सभाओं को सुशोभित करने में अहम भूमिका निभाई.

उत्तर बस्तर डिविजन

रावघाट एरिया

पार्टी स्थापना सप्ताह के मौके पर रावघाट एरिया में तीन जन संगठनों के नेतृत्व में पर्चों, पोस्टरों, बैनरों और दीवाल लेखन के जरिए प्रचार किया गया. गांव स्तर से लेकर एरिया स्तर तक कई आम सभाएं व रैलियां आयोजित की गईं. रैलियों व सभाओं में क्रांतिकारी नाच–गाने व नारे गूंज उठे. इन सभी कार्यक्रमों में 321 महिलाओं, 439 पुरुषों और 31 बच्चों ने भाग लिया. दुश्मन के बलों द्वारा इन कार्यक्रमों में कोई बाधा न पहुंच जाए, इसलिए मिलिशिया के 78 सदस्य सुरक्षा में तैनात थे.

प्रतापुर एरिया

केंद्रीय कमेटी के संदेश के मुताबिक पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर गांव–गांव में पर्चों, पोस्टरों, बैनरों, दीवार लेखन आदि द्वारा व्यापक रूप से प्रचार किया गया. तीनों जन संगठनों, जनताना सरकार, पार्टी व पीएलजीए के नेतृत्व में 5 टीमों ने 3,350 पोस्टरों, 900 पर्चों व 68 बैनरों द्वारा यह प्रचार किया. इस दौरान गांव स्तर की 26 सभाएं और पंचायत स्तर की 4 सभाएं आयोजित हुईं. इन सभी सभाओं में करीब 4600 की तादाद में जनता शामिल हुई.

कुव्वे एरिया

पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रचार के जरिए एरिया के गांव–गांव में क्रांतिकारी जनता तक पार्टी संदेश को पहुंचाया गया. इस दौरान पार्टी निर्माणों को मजबूत करने और पीएलजीए में भर्ती होने का आह्वान किया गया.

किसकोडो एरिया

पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर गश्त के बीच में ही बैनरों, पोस्टरों द्वारा प्रचार किया गया. पार्टी निर्माणों को मजबूत करने, प्रति क्रांतिकारी समाधान योजना को मात देने के पार्टी आह्वान को जनता तक पहुंचाया गया.

पीएलजीए सप्ताह

पश्चिम बस्तर डिविजन

गंगालूर एरिया

पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ को एरिया में समरोत्साह के साथ मनाया गया. इस मौके पर 15–15 लोगों के साथ बनाई गई 7 टीमों ने एरिया में व्यापक तौर पर प्रचार किया. पर्चे, पोस्टर, बैनर और दीवाल लेखन इस प्रचार का हिस्सा बन गए.

गंगालूर एरिया में पीएलजीए सप्ताह का समारोह

बाद में 17 जगहों में पंचायत स्तर की आम सभाओं का आयोजन हुआ, जिनमें 2390 महिलाओं, 3250 पुरुषों, 659 बालिकाओं और 768 बालकों ने शिरकत की. इसी तरह छह जगहों में बड़ी सभाओं का आयोजन हुआ, जिनमें 2656 महिलाएं, 3566 पुरुष, 328 बालिकाएं और 547 बालक शामिल हुए. अपने पारंपरिक हथियार भरमारों, तीर–धनुषों, कुल्हाड़ियों और छूरों से लैस होकर इन समारोहों में भाग लेने वाली जनता ने जनयुद्ध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहरायी.

ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी 'समाधान' हमले को हराने बड़े पैमाने पर पीएलजीए में भर्ती होकर जनयुद्ध को आगे ले जाने का आह्वान इस मौके पर वक्ताओं ने अपने भाषणों के जरिए दिया.

क्रांतिकारी जनताना सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं के लिए इस मौके पर खेल–कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई. जीतने वालों को पुरस्कार भी दिए गए.

पीएलजीए सप्ताह मनाने से रोकने के लिए 1–2 दिसंबर को पुलिस बलों ने कुछ जगहों पर गश्त की. लेकिन मिलिशिया की सतर्क निगरानी में, बिना कोई

परेशानी के पीएलजीए सप्ताह संपन्न हुआ.

भैरमगढ़

2 से लेकर 8 दिसंबर तक एरिया में इस मौके पर जोश–खरोश के साथ सभाओं, रैलियों, पोस्टरों, बैनरों व पर्चों के जरिए प्रचार किया गया. ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी 'समाधान' के खिलाफ जनयुद्ध को तेज करने, और इसके लिए बड़े पैमाने पर पीएलजीए में भर्ती होने की जरूरत को इस प्रचार के मौके पर जनता को अवगत कराया गया.

पीएलजीए दिवस के समारोह में भाग ले रहीं पश्चिम बस्तर की क्रांतिकारी जनता

इस मौके पर कई गांव स्तर व पंचायत स्तर की सभाएं आयोजित की गईं. इन सभी सभाओं में 7187 महिलाएं, 6814 पुरुष, 3030 बच्चियां और 3079 बच्चे कुल मिला कर 20,110 लोग शामिल हुए. एरिया कमेटी और जनताना सरकार कमेटी के नेताओं ने इन सभाओं में भाषण दिए.

प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चार दिन तक खेल–कूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी. इनमें 52 बच्चों ने भाग लिया.

माड डिविजन

डिविजन के कुतुल एरिया में तीन जन संगठनों, जनताना सरकारों और एलओएसों द्वारा पर्चे, पोस्टरों व बैनरों के साथ विशाल जनता में पीएलजीए सप्ताह के बारे में प्रचार किया गया. बाद में अलग–अलग जगहों पर छह सभाएं संचालित की गईं. हर सभा में 2–3 आरपीसियों के गांवों की जनता शामिल हुई. इन सभाओं में 560 महिलाएं और 860 पुरुष शामिल हुए. 55 सीएनएम कार्यकर्ताओं ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति के जरिए इन सभाओं को सफल करने में अहम भूमिका निभाई.

इंद्रावती

पीएलजीए के स्थापना दिवस के मौके पर इंद्रवाती एरिया में एक एरिया स्तर की सभा का आयोजन हुआ. 150 मिलिशिया सदस्यों की सुरक्षा में दिन भर जारी सभा में भाषणों के साथ–साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए. साथ ही रात भर नाच–गानों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे. इस मौके पर 1000 महिलाएं और 3500 पुरुष शामिल हुए.

उत्तर बस्तर डिविजन

रावघाट एरिया

पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ के मौके पर रावघाट एरिया में पोस्टर और बैनरों के साथ प्रचार किया गया. गांव–गांव में सभाओं का आयोजन किया गया. इन सभाओं व प्रचार के जरिए समाधान को हराने व जनयुद्ध को तेज करने के लिए बड़े पैमाने पर पीएलजीए में भर्ती होने का आह्वान युवती–युवकों को दिया गया.

प्रतापुर एरिया

2 दिसंबर – पीएलजीए दिवस के मौके पर तीन जन संगठनों के नेतृत्व में प्रचार किया गया. 850 पर्चों, 990 पोस्टरों व 28 बैनरों के अलावा दीवाल लेखन के साथ यह प्रचार संपन्न हुआ. इसके बाद अलग–अलग जगहों पर आठ सभाओं का आयोजन किया गया. जहां परिस्थिति अनुकूल थी, वहां सीएनएम कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई. इस शपथ कि युवती–युवकों को पीएलजीए में भर्ती होकर जनयुद्ध को तेज करना चाहिए और 'समाधान' को शिकस्त देनी चाहिए, के साथ ये सभाएं संपन्न हुईं. इन सभाओं में लगभग 1000 महिलाएं और 1800 पुरुष और 300 बच्चे शामिल हुए.

कुब्बे एरिया

पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ के मौके पर बैनरों, पोस्टरों व पर्चों के जरिए प्रचार किया गया. इस प्रचार द्वारा 'समाधान' योजना को मात देने, जनयुद्ध को तेज करने और जनताना सरकारों को विस्तार व मजबूत करने का आह्वान किया गया.

किसकोडो एरिया

पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ के मौके पर एरिया में बैनर बांध कर प्रचार किया गया. तीन गांवों में जनता की बैठकें की गईं. बैनरों व सभाओं के जरिए पीएलजीए में भर्ती को बढ़ाने और 'समाधान' को हराने का संदेश पहुंचाया गया.

6 दिसंबर

उत्तर बस्तर डिविजन

किसकोडो एरिया

ज्ञात है कि 6 दिसंबर, 1992 को हिंदुत्व कट्टरपंथियों द्वारा बाबरी मसजिद को ढहाया गया. हर वर्ष इस दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाने जनता का सीपीआई (माओवादी) द्वारा आह्वान किया जाता है. इस आह्वान के तहत किसकोडो एरिया में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों व उत्पीड़ित जनता को एकजुट होकर आवाज उठाने का संदेश जनता तक पहुंचाया गया. ❍

पुलिस हमलें, गिरफ्तारियां व यातनाएं

उत्तर बस्तर डिविजन

रावघाट एरिया में 24–25 सितंबर को थाना पुलिस, बीएसएफ, एसटीएफ और डीआरजी गुंडों ने मिलकर एक बड़ा दमन अभियान चलाया. इस दौरान कई गांवो पर हमलें करके जनता के साथ बेरहमी से मार–पीट की गई. बडपारा के तीन छात्र जब नदी में नहाने जा रहे थे, पुलिस बलों ने पकड़कर यह कहते हुए कि वे नक्सलियों का सहयोग करने जा रहे हैं, बेदम पिटाई की. उसी गावं के

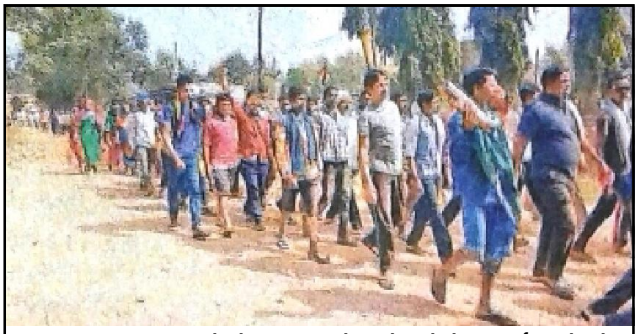

पुलिस जुल्म व अत्याचारों के खिलाफ कोयलीबेड़ा में पैदल मार्च करते लोग

एक किसान जो अपने खेत में जोतने जा रहा था, को पुलिस बलों ने पकड़ा और यह कहते हुए कि वह नक्सलियों के पास जा रहा है, उसके साथ मारपीट की और उससे लगभग पच्चीस किलो कुलथी लूट लिए. गट्टाकल गावं के एक मांझी जो खेत में जोतने के लिए भैंस लेकर जा रहा था, पुलिस बलों के हाथ लग गया. उन्हें स्कूल के अंदर ले जाकर, दरवाजे बंद करके पुलिस बलों ने लात–घूसों और डंडों से उसकी निर्ममतापूर्वक पिटाई की. यहां से शाम को गुंदुल गांव पहुंचे पुलिस बलों ने तड़के तीन बजे गांव को घेर कर 6 ग्रामीणों को उनके घरों से निकाल कर उनके साथ मारपीट की. उसी समय एक महिला के हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालकर धमकी दी गई. बाबूराम आचला नामक व्यक्ति पर झूठा केस लगा कर उसे जेल भेज दिया गया. इस तरह इस अभियान में पुलिस बलों ने 13 ग्रामीणों के साथ मारपीट की. इसके विरोध में 3 अक्टूबर को कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 17 पंचायतों की हजारों जनता ने एकजुट होकर कोयलीबेड़ा थाने का घेराव कर 3 दिन तक आंदोलन किया. इस दौरान आंदोलनकारियों ने जनता के साथ ज्यादती करने वाले पुलिस बलों के ऊपर कार्रवाई करने और कोयलीबेडा थानेदार का तबादला करने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंप दिया.

दक्षिण बस्तर डिविजन

कोंटा एरिया के बालनतोंग पंचायत के गांवों पर 29 अगस्त को पुलिस बलों द्वारा हमलें किए गए. इस दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसी तरह 9 सितंबर को रेगड पंचायत के गांवों पर हमलें करके पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया. 15 सितंबर को अरलमपल्लि पंचायत के दायरे के गांवों पर हमलें करके चार लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया.

पुलिस व अर्ध सैनिक बलों ने 5 सितंबर को किस्टारम एरिया के मइता पंचायत के गांवों पर हमलों के दौरान आतंक मचा कर पांच ग्रामीणों को पकड़, यातनाएं देकर, बाद में छोड़ दिया.

10 सितंबर को किस्टारम एरिया पालचेलिमा एलओएस दायरे के चार पंचायतों के सभी गांवों पर पुलिस व अर्ध सैनिक बलों ने एक साथ हमला करके उत्पात मचाया. इस दौरान बड़ी तादाद में जनता को अपनी हिरासत में ले लिया. डरा–धमकाने व यातनाएं देने के बाद उन्हें छोड़ दिया.

17–18 अक्टूबर को किस्टारम एरिया के पालेमडुगु और कंगलतोंग गांवों पर हमलें करके पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया.

18 अक्टूबर को किस्टारम एरिया के केडवाल गांव पर हमला करके जन संगठन के भूतपूर्व नेता रामाल को गिरफ्तार किया.

24 अक्टूबर को मोर्रुम पंचायत के गांवों पर पुलिस द्वारा हमलें किए गए. इस दौरान पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया.

27 अक्टूबर को कोंटा एरिया के अल्लिगूडेम, जोन्नागूडेम और जीरम गांवों पर हमलें करने वाली पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया.

27 अक्टूबर को किस्टारम एरिया के एंडम गांव पर पुलिस ने हमला करके लोगों के सामान लूट लिए. इस दौरान चार लोगों को पकड़ कर उनके साथ बुरी तरह मार–पीट करके बाद में उन्हें छोड़ दिया.

3 नवंबर को कोंटा एरिया के एलाड गांव के ऊपर हमला करने वाले सरकारी सशस्त्र बलों ने गांव के चालीस लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया. उनमें से 29 के साथ

बुरी तरह मार–पीट करने के बाद सभी लोगों को छोड़ दिया. इसी दिन पुलिस ने कोर्रपाड, गोड्डल और रंगाईगूडा गांवों पर हमलें करके 11 लोगों के साथ मार–पीट की.

5 नवंबर को जगरगुंडा के पुलिस बलों ने कुछ काम पर बोडिकेल से नागारम जा रहे दो मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया.

6 नवंबर को कोंटा एरिया के आंपेंटा गांव पर हमला किया गया. इस दौरान पुलिस ने सभी लोगों को वोट डालने की धमकी देकर चार लोगों को गिरफ्तार किया.

11 नवंबर को जगरगुंडा एरिया चिंतलनार से निकलने वाले पुलिस बलों ने तोंगुम गांव पर हमला करके चार मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया.

पश्चिम बस्तर डिविजन

9 जुलाई को भैरमगढ़ एरिया के मुंडेर गांव पर पुलिस ने हमला किया. इस दौरान मिलिशिया पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई. इसमें मिलिशिया का एक सदस्य घायल हुआ, जबकि दो सदस्य पुलिस के हाथ लग गए. यातनाएं देने के बाद दोनों को जेल में डाल दिया गया.

8 अगस्त की सुबह 6 बजे को भैरमगढ़ एरिया के पोटेम गांव में, मिलिशिया के ऊपर फायरिंग की गयी. बाद में 6 जन को गिरफ्तार किया गया.

9 अगस्त की शाम 6 बजे को भैरमगढ़ एरिया के कोत्रपाल गांव में जनता के ऊपर पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई. हालांकि इस गोलीबारी से बच निकलने में सभी लोग कामयाब हुए.

25 अगस्त के तड़के 3 बजे को भैरमगढ़ एरिया केसूर गांव पर पुलिस बलों ने हमला किया. इस दौरान ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी. बाद में पांच जन को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए.

5 सितंबर को भैरमगढ़ एरिया के जप्पूर गांव पर पुलिस द्वारा हमला किया गया. इस दौरान पुलिस बलों द्वारा जनता पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी में एक किशोर के पेट में गोली लगने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में दो ग्रामीणों जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष हैं, के साथ बुरी तरह मार–पीट की गई.

12 सितंबर को भैरमगढ़ एरिया के अलवूर गांव की मिलिशिया के ऊपर पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाईं.

25–27 अगस्त को गंगालूर एरिया के पिडिया गांव और उसके इर्द–गिर्द के गांवों के दायरे में पुलिस का ऑपरेशन चला. इस दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई.

15 सितंबर को भैरमगढ़ एरिया के बेचापाल गांव को पुलिस ने रातों–रात घेराव करके पांच ग्रामीणों को गिरफ्तार किया.

16 सितंबर की आधी रात को भैरमगढ़ एरिया के केसामुंडे गांव पर पुलिस का हमला हुआ. इस दौरान मिलिशिया के ऊपर अंधाधुंध फाइरिंग की गई. बाद में दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया.

18 सितंबर को पुलिस द्वारा भैरमगढ़ एरिया के गद्दामली गांव पर हमला करके पांच ग्रामीणों के साथ पिटाई की गई.

22–25 सितंबर को गंगालूर एरिया के पुंबाड पंचायत के दायरे में पुलिस का ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान पुलिस ने एक महिला जिसका नाम बुदरी है और एक पुरुष के साथ बुरी तरह माट–पीट की. इसकी वजह से बुदरी बहुत दिनों तक पलंग से उठ नहीं पाई.

2 अक्टूबर को भैरमगढ़ एरिया के कोटमेट्टा गांव पर हमला करने वाले पुलिस बलों ने मिलिशिया कामरेडों पर अंधाधुंध गोलियां चलायी.

24 अक्टूबर को भैरमगढ़ एरिया पुलुम गांव पर पलिस ने हमला करके मिलिशिया के ऊपर फायरिंग की.

25 अक्टूबर को भैरमगढ़ एरिया के पुलोर गांव पर रातों–रात आने वाले पुलिस बलों ने हमला करके पांच लोगों को अपनी हिरासत में लेकर उनके साथ बुरी तरह पिटाई की.

9 नवंबर को भैरमगढ़ एरिया के रेलकल गांव पर हमला करके पुलिस ने जनता पर अंधाधुंध गोलीबारी की. इस दौरान मडकम रंजू को गिरफ्तार किया गया.

9 नवंबर को मद्देड एरिया के सोमनपल्लि पर हमला करके चार लोगों को गिरफ्तार किया गया.

इसी दिन गंगालूर एरिया के मनकेल गांव पर हमला करने वाली पुलिस अपने साथ पांच बकरों को लूटकर ले गई.

18 नवंबर को बुर्गिल के ऊपर हमला करके पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया.

24 नवंबर को पुंबाड और बुर्गिल पर पुलिस ने हमलें करके जनता के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की. हालांकि इस गोलीबारी से किसी तरह अपने–आप को बचाने में लोग सफल हो पाये.

दरभा डिविजन

अक्टूबर में तोंगपाल हाट बाजार गए 62 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर बाद में उनके आत्मसमर्पण की घोषणा की. ❍

जनयुद्ध में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

दंडकारण्य में दिन–ब–दिन बढ़ते दमन के साथ ही जन संघर्ष और जन युद्ध में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. अब संघर्ष यहां की महिलाओं की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. पुलिस बल जब गांवों पर हमलें करते हैं, तो महिलाओं को अपने–आपको बचाने, अपनों को बचाने, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. जब पुलिस किसी को पकड़ती है, छुड़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. पुलिस किसी को मारती है, लाश लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. उतना ही नहीं, दैनिक सामग्री के लिए हाट बाजार जाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ महिलाओं के कंधों पर ही है. हाट बाजार आते–जाते समय भी उन्हें पुलिस दमन का सामना करना पड़ता है और उसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है. यह आम बात हो गई है.

इस वर्ष में महिलाओं द्वारा किए गए संघर्ष के सिलसिले के कुछ अंश जानेंगे.

5–9 जनवरी को पश्चिम बस्तर डिविजन के गंगालूर एरिया में दुश्मन बलों द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया गया था. इस दौरान मुदूम गांव के पास पीएलजीए का घेराव कर पुलिस ने हमला किया, जिसमें पश्चिम बस्तर डिविजन के डीएकेएमएस अध्यक्ष कामरेड बुधराम और मोबाइल मिलिटरी स्कूल की सदस्या कामरेड क्रांति ने शहादत को पाया. हमला करने वाले पुलिस बलों के वापस जाने के तुरंत बाद कुछ महिलाएं घटना स्थल पहुंच गयीं. इधर उधर ढूंढ कर घायल कामरेडों को वहां से सुरक्षित निकाल लायी. गांव की अन्य महिलाओं ने पुलिस बलों का पीछा किया. पुलिस वालों की मारपीट के बावजूद महिलाओं ने आगे बढ़ कर अपने प्रिय जनों की लाश के लिए संघर्ष किया. न सिर्फ उस गांव की महिलाएं बल्कि आस–पास की महिलाएं जिनकी तादाद 400 से अधिक थी, पांच दिन लड़ कर लाशें लेकर आयीं. बाद में क्रांतिकारी रीति–रिवाजों के साथ दोनों कामरेडों का अंतिम संस्कार किया गया.

इस तरह महिलाएं पुलिस के साथ लड़–भिड़ कर इस वर्ष झूठी मुठभेड़ों में मृत पीएलजीए बलों व आम लोगों की 13 लाशें लायीं.

14 फरवरी को गंगालूर एरिया के करका, मदूम, पिडिया, तुमनार और गंपूर गांवों के ऊपर हमलें करके पुलिस ने लगभग 60 महिलाओं के साथ मारपीट की. इसके बावजूद सभी महिलाओं ने हिम्मत से प्रतिरोध करते हुए पुलिस बलों को भगा दिया.

2 जून को रातों–रात आने वाले पुलिस बलों ने हीरिल गांव के नजदीक एंबुश बैठ कर सुबह वहां से जाने वाले पीएलजीए बलों पर हमला किया. इसमें दो कामरेड घायल हुए थे. फाइरिंग की आवाज सुनते ही दौड़ कर आने वाली महिलाओं ने घायल कामरेडों को ढूंढ कर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया.

12 सितंबर को गंगालूर एरिया पेद्दाजोजुर और गुंडम गांवों पर हमलें करने वाले पुलिस बलों ने दो लड़कियों और दो लड़कों को पकड़ा था. लेकिन महिलाओं के संघर्ष की वजह से पकड़े गए लोगों को पुलिस बल अपने साथ नहीं ले जा पाये. गांव की सभी महिलाओं ने चारों तरफ से पुलिस बलों को घेरकर झगड़ा किया, तो पुलिस बलों को अपनी गिरफ्त में मौजूद लोगों को छोड़ना ही पड़ा. महिलाओं के प्रतिरोध को देख कर डरने वाले पुलिस बलों ने उस प्रतिरोध क्षमता को कमजोर करने के लिए महिलाओं को पैसे देने की कोशिश की. लेकिन महिलाओं ने लेने से साफ इनकार कर दिया.

14 सितंबर को पेदाकोरमा गांव पर पुलिस ने हमला किया. उस दौरान इडमे नामक एक युवती जो कुछ समय तक गुरिल्ला दस्ते में काम करके वापस घर जाकर फिलहाल साधारण जिंदगी बिता रही है, को पकड़ कर पुलिस अपने साथ ले गयी. उसे गांव में ही छुड़ाने के लिए महिलाओं ने बेहद कोशिश की. लेकिन सफल नहीं हो पाईं. हालांकि महिलाओं ने हार नहीं मानी. पुलिस का पीछा करते हुए बीजापुर थाना तक जाकर उस युवति को छुड़ा कर लायीं.

26 सितंबर को किरंदूल हाट बाजार से लौटती महिलाओं के सामान की पुलिस ने हमेशा की तरह जांच की. उसी वक्त एक युवक के सामान की जांच कर यह कहते हुए कि वह नक्सलियों के लिए सामान ले जा रहा है, पुलिस ने उसे पकड़ा था. लेकिन महिलाएं उस युवक को पुलिस के हाथों से खींच कर लायीं. ❍

कृपया प्रभात के लिए डिविजनों से सही समय पर निम्नांकित रिपोर्ट्स जरूर भेजें!

- ★ ***अमर शहीदों की जीवनियां जिनके साथ तस्वीरें जरूर संलग्न करें.***
- ★ ***पीएलजीए प्रतिरोध***
- ★ ***जन प्रतिरोध विशेषकर महिला प्रतिरोध***
- ★ ***जन संघर्ष की रपटें***
- ★ ***सभा सम्मेलनों की रपटें***

– संपादक मंडल

''इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है. यह गुस्सा हर सही सोचने वाले इंसान को आना चाहिए!''

– अभिनेता नसीरुद्दीन शाह

ज्ञात है कि उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर में 3 दिसंबर को गोकशी के बहाने हिंसा भड़काई गई थी. इस दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर भी हमला किया था. इस हमले में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत हो गई थी. इस पृष्ठभूमि में जाने माने फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक साक्षात्कार में कहा था, 'मुझे मजहबी तालीम मिली थी. लेकिन रत्ना (उनकी पत्नी) को नहीं. वे लिबरल परिवार से आती हैं. मैं ने अपने बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी. क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना–देना नहीं. मुझे अपने बच्चों के बारे में फिक्र होती है कि कल को उन्हें अगर भीड़ ने घेर कर पूछ लिया कि वह हिंदू है या मुसलमान, उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा. ' उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात की फिक्र होती है कि हालात जल्दी सुधरते नजर नहीं आ रहा है. इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है. यह गुस्सा हर सही सोचने वाले इंसान को आना चाहिए. यह हमारा घर है, हमें यहां से कौन निकाल सकता है.' उन्होंने और भी कहा 'कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत से ज्यादा एक गाय की मौत को अहमियत दी जा रही है.'

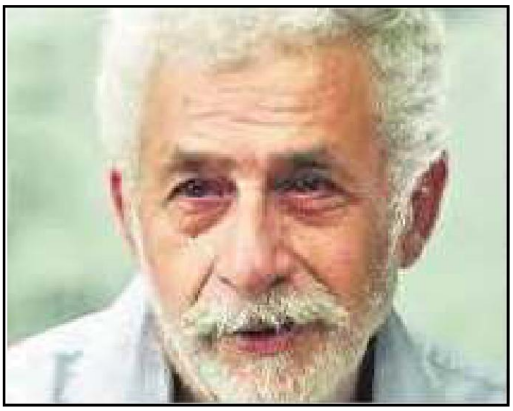

आज, जब देश में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादियों द्वारा जो नफरती माहौल पैदा किया गया है, नसीरुद्दीन की टिप्पणियां बेहद विवादास्पद हो गईं. हिंदुत्ववादियों द्वारा न सिर्फ प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ कई द्वेषपूर्ण कामेंट्स किए गए. यहां तक कि उन्हें गद्दार कह दिया गया. उतना ही नहीं, अभिनेता के खिलाफ भड़के इस विरोध की पृष्ठभूमि में अजमेर साहित्य महोत्सव के आयोजकों ने एक कार्यक्रम को रद्द कर दिया जिसे वे संबोधित करने वाले थे.

इन प्रतिक्रियाओं पर भी बाद में नसीरुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपनी टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा – 'मुझे नहीं मालूम कि इस बार मैं ने ऐसा क्या कह दिया कि मुझे गददार ठहराया जा रहा है. यह बात तो एक चिंतित भारतवासी की हैसियत से मैं पहले भी कह चुका हूं'.

नसीरुद्दीन शाह, शाबाना आज्मी, जावेद अख्तर, अमीर खान, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे कई लोग अपनी प्रतिभा द्वारा भारतीय सिनेमा

उद्योग में अहम भूमिका निभा रहे हैं. इनके पहले भी कई मुसलमान लोगों ने अदाकारों, दर्शकों, लेखकों, गीतकारों, गायकों के रूप में भारतीय सिनेमा में अहम योगदान दिया था. ऐसे में निश्चित रूप से यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि इनके बिना भारतीय फिल्म क्षेत्र अधूरा है. हालांकि अपनी प्रतिभाओं द्वारा भारतीय सिनेमा को परिपूर्णता लाने वाले इन लोगों को हमारे देशवासियों के तौर पर नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के तौर पर दिखाने की साजिशाना कोशिशें संघीय ताकतों द्वारा अक्सर की जाती रही हैं. हिंदू धर्म में पैदा होने वाले कई राजनीतिक नेताओं, पुलिस अधिकारियों, अदाकारों, खिलाडियों द्वारा अक्सर कई बेतुकी बातें, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं. लेकिन उनके खिलाफ उतनी प्रतिक्रियाएं नहीं आती हैं जितनी एक मुसलमान धर्म में पैदा होने वाले आदमी द्वारा जारी एक धर्मनिरपेक्ष व देश हितकारी बयान पर आती हैं.

ऐसे में ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी जो भारत के संविधान के तहत हर नागरिक को प्राप्त होना चाहिए, से बुरी तरह वंचित हो रहे हैं. देश हित में बोलने, प्रतिक्रिया देने, विरोध जताने व संघर्ष करने का अधिकार इस देश के हर किसी को है. यह सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है. जाति, धर्म, लिंग का इस अधिकार या जिम्मेदारी से कोई लेना–देना नहीं है.

हिंदू धर्मोन्माद को भड़काते हुए एवं जाति व लिंग के आधार पर सामाजिक विद्वेष व विभाजन को बढ़ावा देते हुए देश के प्रगतिशील, देशभक्त व जनवादी बुद्धिजीवियों, कलाकारों, तमाम जनपक्षधर लोगों पर हमलें करने की हिंदुत्व फासीवादियों की साजिशों को नाकाम करेंगे व उनका करारा जवाब देंगे. ❍

इस अंक में छपी कुछ तस्वीरें कई दैनिक अखबारों और इंटरनेट से साभार

(आखिरी पेज से...)

इस परिणाम ने पार्टी को और मजबूत, और विस्तार किया. दोनों पार्टियों के गुरिल्ला सेनाओं का विलय होकर मजबूत जनमुक्ति छापामार सेना का गठन हुआ. 2004 तक ही देश में छोटे–छोटे झरनों के रूप में रही कई क्रांतिकारी पार्टियों, ग्रुपों और व्यक्तियों का विलय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट धाराओं के रूप में रही एमसीसीआई और भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) में हो चुका था. इन दोनों मुख्य धाराओं के विलय से एक बड़ा और महान प्रवाह – भाकपा (माओवादी) का उदय हुआ. इस तरह गठित भाकपा (माओवादी) में अत्यंत अनुभवी, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले एंव नक्सलबाड़ी पीढ़ी के नेता भी शामिल हैं. इस तरह के नेता और कतार वाली केंद्रीय कमेटी ने कामरेड गणपति को महासचिव चुन लिया. 2007 में आयोजित एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस के मौके पर भी केंद्रीय कमेटी ने उन्हीं को महासचिव चुन लिया था. एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस के उपरान्त, केंद्रीय कमेटी के नेतृत्व में आंदोलन ने और नयी ऊंचाइयों को छू लिया. विकास के इस क्रम में ही, 2013 के अंत में भाकपा (माले) (नक्सलबाड़ी) और भाकपा (माओवादी) का विलय हुआ, जिससे कहा जा सकता है कि भारत वर्ष में क्रांतिकारी पार्टियों के एकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गयी है.

1992 से 2017 तक कामरेड गणपति ने पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी संभाली थी. इन पूरे 25 सालों के समय में आंदोलन कई ज्वार–भाटाओं का सामना करते हुए केंद्रीय कमेटी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहा. तीखे वर्ग संघर्ष में फौलादी बन गया है. दुश्मन द्वारा संचालित प्रतिक्रांतिकारी हमले को हराने के लिए क्रांतिकारी कतारों और क्रांतिकारी जनता का पार्टी ने दृढ़तापूर्वक नेतृत्व प्रदान किया. कामरेड गणपति इसी क्रम में बढ़ती अपनी अस्वस्थता को पहचान कर, बढ़ती उम्र के साथ आने वाली सीमितताओं को ध्यान में रखकर, महासचिव पद से हटकर, केंद्रीय कमेटी को और मजबूत करने के लक्ष्य से हमेशा की तरह अपनी पूरी शक्ति–क्षमताओं को केंद्रीय कमेटी के साथ–साथ पूरी पार्टी के विकास हेतु इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गए. इसके बाद, केंद्रीय कमेटी ने अपने महासचिव के रूप में कामरेड बसवराजू (नंबाल्ला केशवराव) को चुन लिया. कामरेड बसवराजू साढ़े तीन दशक से भी ज्यादा समय से पार्टी की अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर विभिन्न पार्टी कमेटियों के सचिव के रूप में, पिछले 27 सालों से भी ज्यादा समय से केंद्रीय कमेटी के सदस्य के रूप में और पिछले 18 सालों से पोलित ब्यूरो सदस्य के रूप में सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान करते आ रहे हैं. खासकर, सैनिक क्षेत्र में केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रभारी बनकर जनयुद्ध को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. और ठोस रूप से बताना है तो 1992 के बाद सामूहिक नेतृत्व के रूप में विकसित केंद्रीय कमेटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर अब महासचिव के रूप में विकसित हुए.

पार्टी की केंद्रीय कमेटी में हुए यह बदलाव पूरी पार्टी के विकास क्रम का हिस्सा है. यह बदलाव केंद्रीय कमेटी को और शक्ति प्रदान करेगा. पार्टी की समूची क्रांतिकारी कतारों और क्रांतिकारी जनता से केंद्रीय कमेटी वादा करती है कि वह पार्टी के सांगठनिक उसूल – जनवादी केंद्रीयता और आत्मालोचना–आलोचना को अमल करने में थोड़ी भी ढिलाई न बरतते हुए और दृढ़तापूर्वक अमल करते हुए, पूरी पार्टी कतारों और क्रांतिकारी जनता को सामूहिक व केंद्रीकृत नेतृत्व प्रदान करेगी और 'समाधान' के नाम पर दुश्मन द्वारा फासीवादी तरीके से संचालित प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक हमले को जनदिशा–वर्गदिशा पर निर्भर होकर जनता को जनयुद्ध में गोलबंद कर, हराएगी, देश में नवजनवादी क्रांति को सफल करने के लिए सर्वहारा वर्ग के हिरावल दस्ते के रूप में खड़े होकर नेतृत्व प्रदान करेगी. ❍

अकाल राहत कार्य

ज्ञात है कि बारिश की कमी की वजह से इस वर्ष पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सूखा पड़ा था. इस पृष्ठभूमि में उत्तर बस्तर डिविजन के प्रतापुर एरिया के अकाल पीड़ित किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार कई जगहों पर चक्काजाम व रैलियां की थीं. लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक न रेंगने की वजह से जनता की समस्याएं जस का तस रहीं. इस वजह से जनता ने अपनी तकलीफों को जनताना सरकारों के सामने पेश किया. इसकी प्रतिक्रिया में जनताना सरकार एक तरफ जनता को यह समझाते हुए कि जब तक लुटेरे वर्ग अस्तित्व में रहेंगे तब तक जनता की समस्याएं जारी रहेंगी, अपनी समस्याओं के स्थायी हल के लिए जनता को चाहिए कि वह जनयुद्ध व जन संघर्ष का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि उन्हें आगे ले जाए, दूसरी तरफ जनता की मदद के लिए उसने कमर कसी. जिन्हें खाने की दिक्कत है उनकी मदद करने का निर्णय लिया गया. 78 परिवारों को उनकी हालत और जन संख्या के अनुसार 50 किलों से लेकर 3 क्विंटल तक चावल बांटे गए. इस तरह पूरे एरिया में 32 क्विंटल चावल और 9 क्विंटल धान बांटा गया.

भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) के महासचिव कामरेड गणपति के अपनी जिम्मेदारियों से स्वेच्छापूर्वक हटने के कारण कामरेड बसवराजू को केंद्रीय कमेटी ने अपना नया महासचिव चुन लिया

(भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता कामरेड अभय द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य)

अपनी बढ़ती उम्र और पिछले कुछ सालों से बढ़ती अस्वस्थता को ध्यान में रखकर दूरदर्शिता के साथ केंद्रीय कमेटी को और मजबूत करने के लक्ष्य से महासचिव के पद से स्वेच्छापूर्वक हटने व अपने स्थान पर दूसरे को महासचिव चुनने का प्रस्ताव कामरेड गणपति ने केंद्रीय कमेटी के सामने रखा था. केंद्रीय कमेटी की 5वीं बैठक ने बारीकी से चर्चा कर उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उनके स्थान पर कामरेड बसवराजू (नंबाल्ला केशवराव) को नया महासचिव चुन लिया.

जून 1992 में कामरेड गणपति भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) का महासचिव बन गए थे. उस समय पार्टी बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही थी. 1991 से आंध्रप्रदेश की सरकार ने पार्टी पर दूसरी पारी का दमन शुरू किया था. उस समय में सशस्त्र संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्यनीति अपनायी जाए, इस पर पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही थी. अपनी कमेटी के साथ मिलकर पार्टी के सामने उत्पन्न चुनौतियों व समस्याओं से निपटना तत्कालीन केंद्रीय कमेटी के सचिव कोण्डापल्ली सीतारामैया की बस की बात नहीं थी. इस तरह की परिस्थितियों में समूचे पार्टी कैडरों और जनता पर निर्भर होकर समस्याओं से निपटने की बजाय, कोण्डापल्ली सीतारामैया और एक केंद्रीय कमेटी सदस्य साजिशना तरीकें अपनाकर पार्टी में आंतरिक संकट का कारण बने थे. इस अवसरवादी गुट द्वारा पार्टी का विभाजन करने के लिए की गई कोशिशों को हराने संचालित सूत्रबद्ध संघर्ष में कुछ अवसरवादियों को छोड़कर समूची पार्टी एकत्र होकर खड़ी हुई. इस अवसर पर केंद्रीय कमेटी के युवा नेतृत्व द्वारा आंतरिक संकट का सामना करने हेतु अपनायी गयी पद्धतियां समूची पार्टी के लिए एक बड़ा शिक्षा अभियान साबित हुईं और उन पद्धतियों ने पार्टी की कार्यशैली को सुधार लिया. समूची पार्टी के सैद्धांतिक और राजनीतिक स्तर बढ़ाया. विशेषकर, केंद्रीय कमेटी में सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक कामकाज (फंक्शनिंग) को विकसित किया. केंद्रीय कमेटी में मौजूद क्रांतिकारी नेतृत्व द्वारा संचालित इस पूरे प्रयास में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर कामरेड गणपति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. इस क्रम में ही समूची पार्टी ने एकजुटता दिखायी, षड़यंत्रकारियों को हरा दिया. वह जिन सवालों का सामना कर रही थी, जनवादी केंद्रीयता के उसूल के मातहत उनसे निपटने के लिए तैयार हो गयी. इस परिस्थिति में ही सामूहिक नेतृत्व के रूप उभरी केंद्रीय कमेटी ने कामरेड गणपति को नया महासचिव चुन लिया था.

1995 में हमने अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन आयोजित कर पार्टी लाइन को उन्नत किया. इस अधिवेशन ने नयी केंद्रीय कमेटी को चुन लिया और इस नयी केंद्रीय कमेटी ने कामरेड गणपति को फिर से महासचिव चुना. अगस्त 1998 में भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) और भाकपा (माले) (पार्टी यूनिटी) का विलय होकर नयी भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) का गठन हुआ. इस परिणाम से कई राज्यों में विस्तार होकर पार्टी ने अखिल भारतीय पार्टी का रूप धारण कर लिया. इस मौके पर गठित नयी केंद्रीय कमेटी ने भी कामरेड गणपति को अपना महासचिव चुन लिया. 2 दिसंबर, 2000 तक हमने सैनिक लाइन को विकसित कर जनमुक्ति छापामार सेना को गठित किया. 2001 में आयोजित पूर्ववर्ती भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) की 9वीं कांग्रेस ने पार्टी की राजनीतिक, सैनिक और सांगठनिक लाइन को और मजबूत बनाया. भारत की ठोस परिस्थितियों के साथ दीर्घकालीन जनयुद्ध को जोड़ने के तहत इस अधिवेशन ने छापामार आधार इलाकों (गुरिल्ला बेसों) का निर्माण जैसी नयी अवधारणा बनायी. सीएमसी के मातहत जनमुक्ति छापामार सेना को गठित करने के साथ–साथ जनयुद्ध और राजसत्ता के बीच के संबंध पर पार्टी ने जोर दिया. इस मौके पर गठित नयी केंद्रीय कमेटी ने भी कामरेड गणपति को ही महासचिव के रूप में फिर एक बार चुन लिया.

21 सितंबर, 2004 को भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का विलय होकर भाकपा (माओवादी) का गठन हुआ था. उन्नत सैद्धांतिक और राजनीतिक लाइन पर निर्भर इस विलय के जरिए भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में एक बड़ी छलांग आयी. यह परिणाम भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में ही एक मील का पत्थर है.

(शेष पेज 31 में...)